मई : 2025 वर्ष : 10 अंक : 5

मीडिया मैप

उदार जनतंत्र का सजग प्रहरी

मूल्य : रु 50

हम क्यों...

मीडिया मैप एक वैचारिक पत्रिका है। हमारे समाज के नीतिपरक और मूल्यनिष्ठ बिन्दु तथा इनसे जुड़ाव रखने वाले आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक मुद्दे इसकी विषयवस्तु है। मीडिया मैप की संपादकीय नीति उदारवादी, आधुनिक, प्रगतिशील व सर्व धर्म समभाव की भावना पर आधारित है। मीडिया मैप हमारे बहुलतावादी समाज की विविधताओं से सृजित समस्त सोच, विचार, दृष्टिकोण, मूल्य और मान्यताओं को अपने में समाहित करने का एक प्रयास है । हमारा उद्देश्य वैज्ञानिक सोच द्वारा समाज से जुड़े मूल मुद्दों पर एक प्रबुद्ध जनमत विकसित करना है, जिससे देश में संकुचित मानसिकता और आपसी टकराव से ऊपर उठकर एक उच्चस्तरीय विचार-विमर्श का वातावरण तैयार हो सके।

MEDIA MAP
A Watchdog Of Liberal Democracy

सलाहकार मंडल
डॉ. रामजीलाल जांगिड
डॉ बलदेवराज गुप्त
डॉ जॉन दयाल
डॉ गौहर रजा
मंगल सिंह आजाद

संपादक :**प्रो प्रदीप माथुर**
संयुक्त संपादक : **डॉ सतीश मिश्रा**
सहयोगी संपादक : **प्रो शिवाजी सरकार**
सहायक संपादक **:- सुदामा पाल**
विशेष प्रतिनिधि : **राजीव माथुर**
मुख्य सह-संपादक : **प्रशांत गौतम**
सह-संपादक : **अंकुर कुमार**
लखनऊ संवादाता : **ज़ेबा हसन**
पटना संवादाता : **अजय यायावर**
रायपुर संवादाता : **संदीप कुमार सिंह**

मुख्य प्रबंधक :**जगदीश गौतम**
विधि परामर्शदाता :**संजय माथुर**

पंजीकृत कार्यलय
2325, सेक्टर - डी , पॉकेट - 2 , वसंतकुंज , नई दिल्ली

कार्यालय
69 ज्ञानखंड-4 इंदिरापुरम गाजियाबाद-201014

दूरभाष - **9810385757 / 9910069262**

एम बी के एम फाउंडेशन प्रकाशन

ईमेल-editor@mediamap.co.in

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक प्रदीप माथुर द्वारा लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली से मुद्रित एवं मकान नंबर 70, ज्ञानखंड 4, इंदिरापुरम, जनपद-गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित. सभी विवादों का निस्तारण जिला न्यायालय गाजियाबाद होगा ।

लेखों में उल्लेखित विचार लेखक के अपने हैं। लेखों और विचारो को लेकर किसी तरह का विवाद होने पर पत्रिका के संपादक और प्रकाशक, मुद्रक इसके लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जिला मुख्यालय गाज़ियाबाद ही होगा। इस पत्रिका से जुड़े सभी पदाधिकारी, सहयोगी और लेखक अवैतनिक हैं। पीआरबी एक्ट के तहत अंतर्गत संपादक प्रो प्रदीप माथुर उत्तरदायी है।

संपादकीय
पिछले अंक की एक झलक
विचार प्रवाह
राजनीति परिदृश्य

मुस्लिम-विरोधी ब्रिगेड को मंदिर प्रशासन से झटका	प्रो. प्रदीप माथुर	8
प्रज्ञा ठाकुर को फाँसी की माँग - संघ की राजनीति बेनक़ाब	डॉ. सलीम ख़ान	10
भाजपा की संकीर्ण दृष्टिकोण से उत्तर-दक्षिण विभाजन का खतरा	आर के मिश्रा	11
राणा सांगा के 500 साल पुराने इतिहास पर आज टकराव क्यों?	प्रो प्रदीप माथुर	13
भारतीय राजनीति में वामपंथियों के लिए निर्णायक समय	धर्मेंद्र आज़ाद	15
वक्फ बिल पर एक मुस्लिम महिला का अनुभव	एन सत्या मूर्ति	17

आर्थिक जगत

भारत की विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह में मंदी की आशंका	प्रो शिवाजी सरकार	19
किसान पहचान योजना: कृषि सुधार की दिशा में एतिहासिक कदम	प्रो शिवाजी सरकार	21

अंतराष्ट्रीय मामले

ब्रिटेन को मांगनी चाहिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए माफी	प्रभजोत सिंह	23
पहलगाम त्रासदी : नफरत की तेज़ होती आंधी	प्रो राम पुनियानी	26

व्यक्तित्व

नरेंद्र कुमार माथुर - एक नवोन्मेषी विचारक	एन.के. माथुर	29

कथा साहित्य

खतरे का अंत या मानवता की हार?	दिनेश वर्मा	31

महिला जगत

उत्कृष्ट योगदान के लिए युवा महिला अचीवर्स सम्मानित	सुदामा पाल	33

श्रद्धांजलि

नहीं रहे पूर्व ट्रिब्यून संपादक हरि जयसिंह	मीडिया मैप न्यूज़	36

पिछले अंक की एक झलक

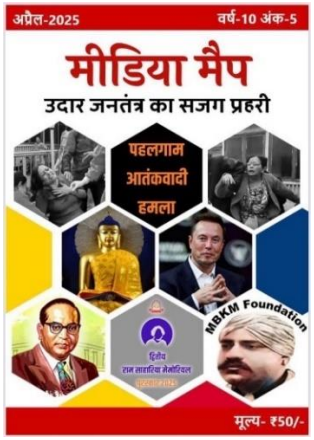

पाकिस्तान पर मंडरा रहे गृह युद्ध के बादल दक्षिण एशिया में शांति के लिए खतरा

तुलसी गबार्ड की यात्रा का अघोषित एजेंडा भारत और अमेरिका के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान का एक हिस्सा हो सकता है, जो कि राष्ट्रपति जो बाइडन के पूर्ववर्ती शासनकाल के दौरान साझा की जाने वाली सूचनाओं की तुलना में कहीं अधिक व्यापक है।

पाकिस्तान में भी जल्द ही इतिहास दोहराया जा सकता है और उसका और अधिक विखंडन हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही भारत के लिए और भी गंभीर खतरे पैदा हो सकते हैं।

~ गोपाल मिश्रा

पूंजीवादी व्यवस्था का संकट : क्या मार्क्स की भविष्यवाणी सच हो रही है ?

पूंजीवादी व्यवस्था मेहनत को नहीं, पूंजी को प्राथमिकता देती है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण बढ़ती बेरोज़गारी है। तकनीकी विकास और ऑटोमेशन का प्रयोग उत्पादन में लागत घटाने और मुनाफ़ा बढ़ाने के लिए होता है, न कि श्रमिकों की सुविधा के लिए। 2024 के अंत तक वैश्विक बेरोज़गारी दर 8% और भारत में 10% से ऊपर पहुँच गई। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की आमदनी में 20% की गिरावट आई, वहीं महंगाई लगातार बढ़ रही है।पूंजीवाद का चरम विरोधाभास यह है कि लाखों मकान खाली पड़े हैं, फिर भी करोड़ों लोग बेघर हैं। गोदामों में अन्न भरा पड़ा है, लेकिन भूख से लाखों लोग पीड़ित हैं। यह सिद्ध करता है कि पूंजीवाद का उद्देश्य समाज की जरूरतों की पूर्ति नहीं, बल्कि मुनाफ़ा है।

-धर्मेन्द्र आज़ाद

भारत का इतिहास और हिंदुत्व की धारणा : एक विश्लेषण

भारत का इतिहास एक जटिल टेपेस्ट्री है, जिसमें विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और राजनीतिक संघर्षों का समावेश है। शिवाजी, हैदर अली, और टीपू सुल्तान जैसे व्यक्तित्वों ने दक्खन के इतिहास को आकार दिया, जबकि अंग्रेजों ने धीरे-धीरे पूरे देश पर नियंत्रण स्थापित किया। यह इतिहास हमें यह सिखाता है कि कैसे धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान ने राजनीतिक घटनाओं को प्रभावित किया और कैसे विभिन्न शक्तियों ने एक-दूसरे के खिलाफ संघर्ष किया। इस प्रकार, भारत का इतिहास न केवल एक संघर्ष की कहानी है, बल्कि यह एक बहु-सांस्कृतिक और बहु-धार्मिक समाज की कहानी भी है, जो समय के साथ विकसित होता रहा है।

-सुरैना अय्यर

पाकिस्तान की दिशाहीन राजनीति

पाकिस्तान की सत्ता-विरोधी तानाशाही अपने स्वतंत्र आलोचकों से निपटने की शैली, जो इससे संबद्ध नहीं है राजनीतिक दलों या शक्तिशाली धार्मिक संगठनों के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तानी अधिकारियों का इससे निपटने का यही तरीका रहा है। लोकतंत्र का चोला ओढ़कर असुविधाजनक आवाजें उठाई जा रही हैं। बलूचिस्तान और जनजातीय क्षेत्र की दयनीय स्थिति पर पूरे पाकिस्तान में समाज के विभिन्न वर्गों का समर्थन प्राप्त है। फिर भी इन उदारवादियों के साथ किए गए व्यवहार के खिलाफ पर्याप्त विरोध विचारकों और कार्यकर्ताओं की कमी क्यों है? आम शिकायत यह है कि इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे इस पर चिंता व्यक्त करते हैं।

-जगदीश गौतम

****

संपादकीय

मई दिवस: अंतरराष्ट्रीय चेतना और भारत में घटती प्रासंगिकता

प्रो. प्रदीप माथुर

पूँजीवाद के वैश्विक केंद्र और आर्थिक साम्राज्यवाद के सर्वोच्च शिखर पर बैठे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई वाली व्यवस्था में भी इस वर्ष मई दिवस अत्यंत उत्साह और सक्रियता के साथ मनाया गया। अमेरिका, जो श्रमिक आंदोलन की पृष्ठभूमि में एक समय विरोध का चेहरा रहा है, आज श्रमिक चेतना का अंतरराष्ट्रीय मंच बनता जा रहा है। देश के सभी 50 राज्यों में विशाल रैलियाँ निकाली गईं जिनमें लाखों नागरिकों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया।

ट्रंप सरकार की नीतियों के विरोध में एकजुट हुए 50,501 संगठनों ने 1 मई को "विरोध दिवस" के रूप में मनाते हुए मई दिवस को एक नई परिभाषा दी। इन संगठनों ने यह स्पष्ट किया कि मई दिवस केवल ऐतिहासिक परंपरा नहीं, बल्कि आज भी एक जीवंत और प्रासंगिक आंदोलन है, जिसका उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें और अधिक अधिकार दिलाने की माँग करना है। उन्होंने इसे एक ऐसा अवकाश कहा "जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों के लिए मनाया जाता है और हम इस दिन पर श्रमिक अधिकारों की लड़ाई को और तेज़ करेंगे।"

यह देखकर हर्ष होता है कि विकसित राष्ट्रों में जहाँ पूंजीवाद का वर्चस्व है, वहाँ भी सामाजिक न्याय और श्रमिक अधिकारों की आवाज़ बुलंद की जा रही है। किंतु दूसरी ओर जब हम भारत की स्थिति का अवलोकन करते हैं, तो हालात काफी. चिंताजनक हैं।

भारत में, जहाँ बेरोज़गारी और महँगाई दोनों अपने चरम पर हैं, वहाँ मई दिवस की उपेक्षा गंभीर प्रश्न खड़े करती है। एक समय था जब भारत में मई दिवस श्रमिकों की चेतना, संगठन और अधिकारों का प्रतीक हुआ करता था। आज वही दिन कई जगहों पर मात्र एक अवकाश बनकर रह गया है — न रैलियाँ होती हैं, न जनचेतना अभियान, और न ही श्रमिकों के मुद्दों पर कोई सार्वजनिक विमर्श।

ऐसे समय में जब देश का एक बड़ा तबका अनुबंध, ठेका और असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा है और श्रम कानूनों में पूंजीपति पक्षीय सुधार कर रही हैं, ऐसे में मई दिवस का महत्व पहले से कहीं अधिक होना चाहिए था। यह दिन उन तमाम कामगारों की आवाज़ है, जिन्हें आज भी न्यूनतम मज़दूरी, सामाजिक सुरक्षा और गरिमा से जीवन जीने का अधिकार नहीं मिला है।

प्रश्न यह है कि इस गिरती हुई प्रासंगिकता के लिए ज़िम्मेदार कौन है? क्या यह श्रमिक संगठनों की निष्क्रियता है? क्या यह राजनीतिक नेतृत्व की उदासीनता है? या फिर एक समाज के रूप में हमने मेहनतकश तबकों की आवाज़ को सुनना बंद कर दिया है?

अब समय आ गया है कि मई दिवस को फिर से उसकी असली आत्मा भाव के साथ मनाया जाए। यह दिन मात्र श्रमिक का प्रतीक नहीं, बल्कि उनके संघर्ष, एकता और अधिकारों की पुनर्स्थापना के दिन के रूप में स्थापित हो. रैलियों से आगे बढ़कर इस दिवस को नीतिगत विमर्श और सामाजिक आंदोलन से जोड़ा जाए। तभी मई यानी मजदूर दिवस फिर से वह अर्थ और ताकत पा सकेगा जो कभी इसकी पहचान हुआ करती थी।

प्रो प्रदीप माथुर

गोबर में लिपटी भारतीय शिक्षा : भगवाकरण अभियान जोरों पर

~धर्मेन्द्र आजाद

हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के लक्ष्मीबाई कॉलेज में जो 'गोबर अनुष्ठान' आयोजित हुआ, वो सिर्फ़ हास्यास्पद नहीं, बल्कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था की सड़ांध मारती सच्चाई का एक जीवंत उदाहरण भी है। कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ. प्रत्यूषा वसाला ने कुछ क्लासरूम्स की दीवारों पर गोबर पुतवाया, और ख़ुद भी हाथ बँटाया, और गर्व से इसे 'प्राचीन लेकिन आज भी प्रासंगिक टेक्नोलॉजी' बताया — उनका दावा था कि इससे कमरे ठंडे रहते हैं। अब अगला कदम शायद ये हो कि कंप्यूटर वायरस भगाने के लिए CPU पर गंगाजल छिड़का जाए और हार्ड डिस्क पर तुलसी की माला बांध दी जाए।

प्रिंसिपल मैडम के इस 'ज्ञान यज्ञ' के उत्तर में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष और छात्रों ने भी 'श्रद्धापूर्वक' इस परंपरा का सम्मान' किया — और उन्हीं के कार्यालय की दीवारों को गोबर से विभूषित कर दिया। उनका कहना था कि यदि गोबर इतना लाभकारी है, तो इसका पहला फायदा कॉलेज की मुखिया को ही मिलना चाहिए, क्योंकि यह ज्ञान गंगा तो उन्हीं के दिमाग़ से निकली है। यह घटना सिर्फ एक मज़ाक नहीं, बल्कि उस गंभीर और भयावह प्रक्रिया की झलक है, जिसमें शिक्षा अब किताबों से नहीं, दीवारों पर चढ़ाए जा रहे गोबर से संचालित हो रही है — और वो भी एक ख़ास विचारधारा के रंग में रंगी हुई।

नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के नाम पर जो परिवर्तन किए गए हैं, वे 'भारतीयकरण' या 'संस्कृतिकरण' की आड़ में दरअसल वैज्ञानिक सोच की निर्मम हत्या हैं। CBSE के पाठ्यक्रम से डार्विन का विकासवाद, आवर्त सारणी, फ्रेंच क्रांति, मुग़ल इतिहास और लोकतांत्रिक आंदोलनों जैसे महत्वपूर्ण विषयों को हटा दिया गया है — वो सारे हिस्से जो छात्रों को सोचने, तर्क करने और प्रगतिशील बनने की ताक़त देते थे। अब शिक्षा तर्क का नहीं, आस्था का विषय बना दी गई है। "वेदों में सब था" का राग अलापकर छात्रों को प्रयोगशालाओं से यज्ञशालाओं की ओर धकेला जा रहा है। सवाल पूछना अब राष्ट्रद्रोह है, और गोबर पोतना संस्कृति प्रेम।

लेकिन हमला केवल पाठ्यक्रमों तक सीमित नहीं है — शिक्षा प्रणाली की रीढ़ को भी योजनाबद्ध तरीके से तोड़ा जा रहा है। 2024-25 के बजट में उच्च शिक्षा के लिए आवंटन में 17% और UGC के लिए 61% की कटौती की गई है। भारत पहले ही शिक्षा पर GDP का बेहद कम हिस्सा खर्च करता है — और अब उसे और घटाया जा रहा है। 2014 से 2023 के बीच 89,441 सरकारी स्कूल बंद किए जा चुके हैं।

ईदः साम्प्रदायिक सौहार्द की मिसाल

~मोहम्मद अकरम

ईद पर कई जगहों पर हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली। अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर मामले के पूर्व पक्षकारों ने एक-दूसरे के गले मिलकर प्रेम और सद्भाव का संदेश दिया। जयपुर, प्रयागराज, वाराणसी और संभल जैसे शहरों में हिंदुओं ने ईद की नमाज़ अदा करने के बाद मस्जिदों से बाहर निकलते समय मुसलमानों पर फूल बरसाए। मुंबई में पुलिस और नमाज़ियों ने शांति और सद्भावना के प्रतीक के रूप में एक-दूसरे को गुलाब के फूल दिए।

राजस्थान के जयपुर में दिल्ली रोड स्थित ईदगाह से लौट रहे मुसलमानों पर हिंदू निवासियों ने फूल बरसाकर भाईचारे का खूबसूरत नजारा पेश किया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

इसी तरह प्रयागराज में भी सामाजिक संगठनों ने मस्जिद से बाहर निकलते ही नमाजियों पर फूल बरसाकर अपनी एकजुटता दिखाई। फूलों की वर्षा के दौरान कई किलो गुलाब की पंखुड़ियों का इस्तेमाल किया गया और नमाजियों को ईद की मुबारकबाद देने के लिए गुलाब के फूल भी दिए गए।

मुंबई में नमाज के बाद मुसलमानों ने एक-दूसरे को गुलाब के फूल बांटे और कई नमाजियों और बच्चों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों को फूल बांटे, जिससे उनके चेहरों पर मुस्कान आ गई।

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के संधी कस्बे में ईद के जुलूस के दौरान हिंदुओं ने मुसलमानों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। रिपोर्ट के अनुसार, जब ईद का जुलूस नवाबगंज मोहल्ले में पहुंचा, तो हिंदू निवासियों ने छतों से जुलूस पर फूल बरसाए। स्थानीय नगर पालिका अध्यक्ष रामजी गुप्ता ने जुलूस में शामिल सभी लोगों का गर्मजोशी से स्वागत किया। दिल्ली के सीलमपुर से भी वीडियो सामने आए, जिसमें हिंदू समुदाय के लोग नमाजियों पर फूल बरसाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा-जमुनी तहजीब (हिंदू-मुस्लिम एकता की संस्कृति) की एक असाधारण मिसाल देखने को मिली। ईद की नमाज अदा करने के बाद जब मुसलमान मस्जिद से बाहर निकले तो हिंदुओं ने उन पर फूल बरसाए, जिससे एकता की भावना और मजबूत हुई।

संभल में ईदगाह की ओर जा रहे नमाजियों पर फूल बरसाए गए और दादरी में हिंदुओं ने मुसलमानों को फूल भेंट किए। इन घटनाओं के सोशल मीडिया वीडियो खूब शेयर किए गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राज कुमार भाटी ने कहा कि दादरी का इलाका हमेशा से हिंदू-मुस्लिम भाईचारे की मिसाल रहा है, जो सांप्रदायिक तनाव से मुक्त रहा है।

अयोध्या (फैजाबाद) में ईद-उल-फितर पर सांप्रदायिक सौहार्द का अनूठा नजारा देखने को मिला। बाबरी मस्जिद-राम मंदिर विवाद में पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी और महंत धर्मदास ने एक-दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। संत समुदाय ने प्रेम और एकता का संदेश देने के लिए इकबाल अंसारी के घर का दौरा भी किया।

इस बीच, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुस्लिम समुदाय को ईद की बधाई देने के लिए कोलकाता के रेड रोड का दौरा किया।

मुस्लिम-विरोधी ब्रिगेड को मंदिर प्रशासन से झटका

~प्रो. प्रदीप माथुर

प्रो. प्रदीप माथुर

जब पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की हत्या ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया है और हम सभी भय और अनिश्चितता के तनावपूर्ण वातावरण में जी रहे हैं, तब स्वाभाविक रूप से किसी सकारात्मक खबर को नजरअंदाज कर देना आसान हो जाता है। लेकिन संयोगवश मुझे हाल ही में एक छोटी, लेकिन दिल को छू जाने वाली खबर मिली जिसने मेरा दिन बना दिया। लंबे समय बाद मुझे देश के मौजूदा नफरत भरे माहौल, सांप्रदायिक तनाव और जातीय-धार्मिक राजनीति के बीच एक आशा की किरण दिखाई दी।

यह खबर न तो न्यूयॉर्क से है, जहाँ संयुक्त राष्ट्र महासचिव और कई वैश्विक नेताओं ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है, और न ही कनाडा से, जहाँ प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बहाल करने की उम्मीद जगाई है और जनादेश प्राप्त किया है। बल्कि यह दिल को सुकून देने वाली खबर हमारे घरों के पास की है – वृंदावन

से, जो मथुरा जिले का एक प्रसिद्ध मंदिर नगर है। यह खबर खास इसलिए भी है क्योंकि यह उन सांप्रदायिक हिंदुत्ववादी तत्वों को करारा जवाब है, जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले ने उन्हें एक और बहाना दे दिया है अपनी मुस्लिम-विरोधी रट लगाने का।

हाल ही में नफरत फैलाने वाले इन गुटों ने मथुरा और वृंदावन जैसे पवित्र नगरों में बैठकें की हैं, जहाँ हिंदू दुकानदारों और तीर्थयात्रियों से मुसलमानों से किसी भी तरह का व्यापारिक संबंध न रखने की अपील की गई। उन्होंने मुस्लिम दुकानदारों से अपने प्रतिष्ठानों पर मालिक का नाम लिखने की भी माँग की।

लेकिन प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर ने इन नफरत फैलाने वाले लोगों के सुझाव को सख्ती से खारिज कर दिया है कि मुसलमानों को जो मंदिर में सेवाएं दे रहे हैं, उनका बहिष्कार किया जाए।

मंदिर के पुजारी और प्रशासन समिति के सदस्य ज्ञानेंद्र किशोर गोस्वामी ने बताया कि मुसलमान, खासकर मुस्लिम कारीगर और बुनकर, दशकों से भगवान बांके बिहारी (कृष्ण भगवान) के वस्त्र बुनने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। वे जटिल मुकुट, चूड़ियाँ जैसी

वस्तुएँ बनाते हैं, जिन्हें भगवान और उनके दर्शन के लिए आने वाले देश-विदेश के भक्तों को अर्पित किया जाता है। इतना ही नहीं, कई मुसलमान बांके बिहारी जी के प्रति गहरी श्रद्धा रखते हैं और अक्सर मंदिर में दर्शन करने आते हैं।

इसके अलावा गोस्वामी ने कहा कि वृंदावन में हिंदू और मुस्लिम हमेशा शांति और सौहार्द से रहते आए हैं और यहाँ कभी सांप्रदायिक तनाव नहीं रहा। मंदिर नगर के अधिकांश पुजारियों और स्थानीय नेताओं ने गोस्वामी की बात का समर्थन किया है, जिससे नफरत फैलाने वालों को बड़ा झटका लगा है।

मंदिर के पास के दुकानदार – चाहे हिंदू हों या मुस्लिम – कहते हैं कि उन्हें एक-दूसरे से कोई समस्या नहीं है। बल्कि वे एक-दूसरे की मदद करते हैं। एक मुस्लिम दुकानदार ने कहा कि बांके बिहारी जी की कृपा से वे शांति से रहते हैं और अच्छा व्यापार करते हैं।

कई प्रतिष्ठित लोगों ने मुस्लिम-विरोधी हिंदुत्ववादी ब्रिगेड की नफरत की मुहिम के खिलाफ बयान दिए और अभियान चलाए हैं। लेकिन बीजेपी-आरएसएस समर्थित आईटी सेल के अमित मालवीय जैसे तत्व यह दावा करते रहे हैं कि उन्हें सभी सच्चे धार्मिक हिंदुओं और पुजारियों का समर्थन प्राप्त है और जो लोग सांप्रदायिकता के खिलाफ बोलते हैं, उन्हें 'हिंदू-विरोधी' और 'राष्ट्र-विरोधी' करार देते हैं। ऐसे में बांके बिहारी मंदिर प्रशासन का यह करारा जवाब इस नफरत फैलाने वाले गिरोह की हवा निकाल देता है।

मंदिर प्रशासन द्वारा लिया गया यह रुख न केवल न्यायसंगत और निष्पक्ष है, बल्कि व्यावहारिक भी है। नफरत फैलाने वाले हिंदुत्व ब्रिगेड की अगुवाई करने वाले छोटे-बड़े बीजेपी नेताओं को हमारे जमीनी स्तर की अर्थव्यवस्था की सच्चाई का कोई ज्ञान नहीं है।

मंदिर प्रशासन द्वारा लिया गया यह रुख न केवल न्यायसंगत और निष्पक्ष है, बल्कि व्यावहारिक भी है। नफरत फैलाने वाले हिंदुत्व ब्रिगेड की अगुवाई करने वाले छोटे-बड़े बीजेपी नेताओं को हमारे जमीनी स्तर की अर्थव्यवस्था की सच्चाई का कोई ज्ञान नहीं है।

1980 के दशक के अंत में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान जब बड़ी संख्या में हिंदू भक्त अयोध्या में अस्थायी रामलला मंदिर में पूजा करने आने लगे, तब स्थानीय मुसलमानों को कोई डर नहीं था, बल्कि वे खुश थे। जब दिसंबर 1992 में अराजक तत्वों ने ढांचा गिरा दिया और देश के कई हिस्सों में हिंसा भड़क उठी, तब भी अयोध्या और उसके आस-पास के क्षेत्रों में शांति बनी रही। यह बात कई लोगों को आश्चर्यचकित कर गई।

इसका कारण यह था कि रामलला मंदिर में पूजा के लिए आने वाले भक्तों को रामनवमी (भगवा रंग का बड़ा हाथ से बुना गया अंगवस्त्र, जिसमें रामायण के श्लोक बुने होते हैं) और लकड़ी की खड़ाऊँ की आवश्यकता होती थी – और ये दोनों वस्तुएँ मुसलमान बनाते हैं – कपड़ा मुस्लिम बुनकर और खड़ाऊँ मुस्लिम बढ़ई। उनका व्यापार खूब चला और उन्होंने अच्छा पैसा कमाया। हिंदू भक्तों को कभी यह आपत्ति नहीं रही कि वे मुसलमानों द्वारा बनाई गई वस्तुएँ पहनें – बल्कि इस पर कभी चर्चा भी नहीं हुई।

मुस्लिम-विरोधी नफरत और विचारधारा बीमार मानसिकता का परिणाम है और इसका डटकर विरोध होना चाहिए। अत्यधिक पूजनीय बांके बिहारी मंदिर ने इसका मार्ग दिखा दिया है।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार , मीडिया गुरु एवं मीडिया मैप के संपादक हैं।

प्रज्ञा ठाकुर को फाँसी की माँग - संघ की राजनीति बेनक़ाब

~डॉ. सलीम ख़ान

डॉ. सलीम ख़ान

एनआईए कोर्ट द्वारा मालेगाँव बम धमाके के सात अभियुक्तों, जिनमें पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी शामिल हैं, को सज़ा-ए-मौत देने की माँग करना अपने आप में एक चौंकाने वाली घटना है। यह निर्णय सिर्फ अभियुक्तों को सजा देने का मामला नहीं, बल्कि उस फ़र्ज़ी "हिंदू आतंकवाद नहीं होता" वाले नैरेटिव के अंत का प्रतीक है, जिसे हेमन्त करकरे की निडर और ईमानदार जाँच ने पहली बार उजागर किया था।

हेमन्त करकरे की अगुवाई में एसआईटी ने समझौता एक्सप्रेस, अजमेर दरगाह, मक्का मस्जिद और मालेगाँव धमाकों में हिंदू कट्टरपंथियों की संलिप्तता साबित की थी। उन्होंने 'अभिनव भारत' और संघ से जुड़े लोगों की भूमिका बेनक़ाब की। इसी जाँच की वजह से उन्हें रास्ते से हटाने की साज़िश हुई और उनकी हत्या कर दी गई—ऐसा आरोप भी बार-बार सामने आता रहा है।

उनकी विधवा कविता करकरे को जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो करोड़ रुपये का ऑफ़र भेजा, तो उन्होंने उस प्रस्ताव को ठुकराकर स्वाभिमान की मिसाल पेश की। वहीं कांग्रेस नेता अब्दुर्रहमान अन्तुले को संसद में यह सवाल उठाने पर कि करकरे को उस गली में जाने का आदेश किसने दिया, मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा।प्रज्ञा ठाकुर, जिनकी मोटरसाइकिल का उपयोग धमाके में हुआ, ने दावा किया था कि करकरे उनकी "शाप" से मरे हैं। बाद में बीजेपी ने उन्हें भोपाल से लोकसभा चुनाव में उतारा और जिताया, जबकि वे आतंकवाद के गंभीर आरोपों में घिरी थीं। उन्होंने संसद में गोडसे की तारीफ़

कर प्रधानमंत्री को शर्मिंदा किया, लेकिन फिर भी उन्हें संसद की रक्षा समिति में शामिल किया गया। हालांकि समय के साथ बीजेपी हाईकमान उनसे किनारा करता गया। बीमार होने का दावा कर ज़मानत लेनेवाली प्रज्ञा को कभी फ़ुटबॉल खेलते तो कभी नाचते हुए देखा गया, जिससे उनकी बीमारी पर सवाल उठे। बाद में उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी हुआ। अब एनआईए ने मालेगाँव धमाके में शामिल सातों अभियुक्तों के लिए मौत की सज़ा की माँग करते हुए कोर्ट में याचिका दी है। एजेंसी ने यूएपीए की धारा 16 के तहत यह दलील दी है कि आतंकवादी हमले में लोगों की मौत हुई है, इसलिए अपराधियों को फाँसी दी जानी चाहिए। यही धारा अजमल कसाब पर भी लागू हुई थी। इन अभियुक्तों में प्रज्ञा ठाकुर के अलावा मेजर रमेश उपाध्याय, कर्नल पुरोहित, अजय राहिरकर, जगदीश म्हात्रे, सुधाकर द्विवेदी और सुधाकर चतुर्वेदी शामिल हैं। आरोप है कि इन सभी ने विस्फोटक सामग्री, प्रशिक्षण और साज़िश की योजना में सक्रिय भूमिका निभाई।

विशेष सरकारी वकील ने 1839 पृष्ठों की बहस और 53 पन्नों का तर्कपत्र कोर्ट को सौंपा है। जाँच और सुनवाई 17 वर्षों तक चली, जिसमें 323 गवाहों के बयान दर्ज हुए। कुछ गवाह मुकर गए, लेकिन इससे बचाव पक्ष को कोई लाभ नहीं हुआ। प्रज्ञा पर भारतीय दंड संहिता, एक्सप्लोसिव एक्ट, आर्म्स एक्ट और यूएपीए के तहत मुकदमा जारी है।

यह केस भारत में आतंकवाद को धार्मिक चश्मे से देखने की सोच के खिलाफ एक बड़ा उदाहरण है। करकरे की मेहनत से मालेगाँव धमाके में फँसाए गए बेक़सूर मुस्लिमों को बरी किया गया और असली अपराधी सामने लाए गए। बाद में जब 2011 में जाँच एनआईए को सौंपी गई, तो उसने 2016 में प्रज्ञा और कुछ अन्य आरोपियों को क्लीन चिट देने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने केवल कुछ को ही बरी किया। अब वही एनआईए यू-टर्न लेते हुए फाँसी की माँग कर रही है।

भाजपा की संकीर्ण सोच से उत्तर-दक्षिण विभाजन का खतरा

~आर के मिश्रा

आर के मिश्रा

कहा जाता है कि घमंड तर्क का दलदल है। यह कीचड़ में धंस जाता है। कई गौरव की चाहत रखने वाले राजनीतिक जुए की शुरुआत सुप्त अंगारों को हवा देने से हुई, लेकिन बाद में पता चला कि आग की लपटें उनके सपनों पर गिरती राख की काली धुंध की तरह उतर आईं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत तीन भाषाओं के फार्मूले को लागू न करने को लेकर केंद्र और तमिलनाडु के बीच शुरू हुई तनातनी ने अब दक्षिणी राज्यों के लिए महत्वपूर्ण कई अन्य मुद्दों को भी अपनी चपेट में ले लिया है।

चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश को छोड़कर बाकी सभी राज्य- केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु एक मंच पर आ गए हैं। देश के दक्षिणी राज्यों में बढ़ती बेचैनी सीमा पार कर दूसरे विपक्षी राज्यों के नेताओं और राजनीतिक संस्थाओं को भी अपनी चपेट में ले रही है, यह भाजपा शासित केंद्र के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, जो नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैसाखियों पर टिका हुआ है। वक्फ संशोधन विधेयक पर चुप्पी के लिए दोनों को नोटिस दिया गया है।

22 मार्च को कई राज्यों के नेता दक्षिणी राज्यों में परिसीमन के ज़रिए लोकसभा सीटों की संख्या कम करने की भाजपा की कोशिश के ख़िलाफ़ एकजुटता दिखाने के लिए एक साथ आए। उन्होंने कहा, "वह देश के उत्तरी हिस्से में सीटें जीतकर सत्ता में बने रहने के लिए ऐसा कर रही है।" इस उद्देश्य के लिए गठित संयुक्त कार्रवाई समिति ने

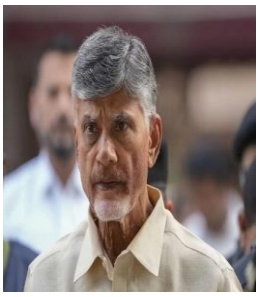

1971 की जनगणना के आधार पर इस रोक को 25 साल और बढ़ाने की मांग की है।

बैठक की मेजबानी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने की और इसमें केरल, तेलंगाना और पंजाब के मुख्यमंत्री क्रमशः पिनाराई विजयन, रेवंत रेड्डी और भगवंत मान, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, भारत राष्ट्र समिति के नेता केटी रामाराव और बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक (वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से) सहित अन्य ने भाग लिया।

एक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन ने अनुमान लगाया है कि जब दक्षिण उत्तर के लिए भुगतान करने या उसके राजनीतिक वर्चस्व के अधीन होने से इनकार करता है, तो देश के उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों के बीच विचलन भारतीय संघ में तनाव पैदा करता है। वित्तीय संसाधनों का पुनर्वितरण एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है, न केवल देश के क्षेत्रवार बहुत असमान विकास के कारण बल्कि जनसांख्यिकीय कारणों से भी। भारत में, मुख्य कर केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए जाते हैं, जो फिर एक जटिल वितरण प्रणाली को ध्यान में रखते हुए राज्यों को धन आवंटित करता है।

"विपरीत क्षेत्रीय गतिशीलता की चुनौती" शीर्षक वाला अध्ययन भारत पर केंद्रित है और इसका नेतृत्व पेरिस स्थित स्वतंत्र थिंक-टैंक इंस्टीट्यूट मॉन्टेन में भारत के एक वरिष्ठ फेलो डॉ क्रिस्टोफ जैफरलॉट ने किया

है। यह बताता है कि पांच दक्षिणी राज्य जो बहुत अधिक करों का भुगतान करते हैं, उन्हें बदले में बहुत कम मिलता है। "पांच दक्षिणी राज्यों ने अपनी कम जनसंख्या वृद्धि दर और शहरीकरण के उच्च स्तर के कारण सबसे अधिक नुकसान उठाया है। केरल ने 12वें और 15वें वित्त आयोगों के बीच इसे आवंटित धन का 27.7 प्रतिशत और तमिलनाडु ने 23.1 प्रतिशत खो दिया। आज, जब हम किसी राज्य में उसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के रूप में कर संग्रह और नई दिल्ली से प्राप्त राशि के बीच के अंतर की गणना करते हैं, तो हम पाते हैं यह अध्ययन काफी विस्तृत है तथा अपने तर्क को पर्याप्त आंकड़ों से पुष्ट करता है।

उत्तर-दक्षिण विभाजन की गूंज बढ़ती जा रही है। स्टालिन दक्षिण के लिए एक "द्रविड़" मॉडल की वकालत कर रहे हैं, जिसमें मानव पूंजी में प्राथमिकता वाले निवेश पर जोर दिया जा रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पहले ही कर वसूली की निंदा की है, जिससे दक्षिण को नुकसान हो रहा है और उत्तर को लाभ हो रहा है। "दक्षिणी राज्यों के मंच" के विचार पर चर्चा हो रही है। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारणों से तनाव बढ़ने की संभावना है।

वैसे भी, हिंदी विरोधी आंदोलन 1937 से तमिलनाडु के सामाजिक ताने-बाने का एक सतत हिस्सा रहा है, जब मद्रास प्रेसीडेंसी के स्कूलों में इसकी पढ़ाई अनिवार्य कर दी गई थी, जिससे समय-समय पर उथल-पुथल होती थी। जनवरी 1965 में, आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया और दो पुलिसकर्मियों सहित 70 लोग मारे गए, जिसके बाद तत्कालीन प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री को आश्वासन जारी करना पड़ा कि जब तक गैर-हिंदी राज्य चाहेंगे, तब तक अंग्रेजी आधिकारिक भाषा बनी रहेगी। आधिकारिक भाषाओं के रूप में हिंदी और अंग्रेजी के उपयोग की गारंटी देने के लिए इंदिरा गांधी सरकार ने 1967 में

> तीन भाषा नीति और वक्फ संशोधन विधेयक जैसे मुद्दों पर केंद्र और दक्षिणी राज्यों के बीच टकराव गहराता जा रहा है। तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्य अब एकजुट होकर राजनीतिक और आर्थिक असमानताओं के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। हिंदी थोपे जाने और संसाधनों के असमान वितरण जैसे मुद्दे उत्तर-दक्षिण तनाव को और भड़का रहे हैं। यह लेख तमिलनाडु की अगुवाई में उभरते "द्रविड़ मॉडल" और केंद्र की नीतियों पर दक्षिण की तीखी प्रतिक्रिया का विश्लेषण करता है, जो भारतीय संघ की एकजुटता पर सवाल उठाता है।

आधिकारिक भाषा अधिनियम में संशोधन किया था। उसी वर्ष कांग्रेस ने डीएमके के हाथों सत्ता खो दी और उसके बाद कभी भी पहले जैसा दर्जा हासिल नहीं कर पाई। हिंदी के प्रचार के गुप्त और साथ ही प्रकट प्रयास जारी हैं।

नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली बीजेपी 2023 में दक्षिण में अपना एकमात्र गढ़ कर्नाटक कांग्रेस के हाथों गंवाने के बाद दक्षिणी राज्यों की गिनती से बाहर हो गई। उसी साल बाद में तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति (बीएचआरएस) कांग्रेस के सामने झुक गई। भगवा दल अब ऑस्ट्रेलिया में पैर जमाने के लिए बेताब है। पश्चिम बंगाल में करारी हार, हरियाणा में मजबूती और दिल्ली में आप से बुरी तरह हारने के बाद, बीजेपी अब बिहार पर नज़र गड़ाए हुए है, जहां इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। हालांकि यह काफी पीछे है, फिर भी यह 2026 में होने वाले चुनावों से पहले तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को हमेशा उबाल पर रखना चाहता है। और यहीं पर पेंच फंसा हुआ है।

केंद्र ने सुलगती राख को और हवा दी है और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को 2,152 करोड़ रुपये के समग्र शिक्षा कोष को रोककर एक ज्वलंत मुद्दा सौंप दिया है क्योंकि उसने अपने स्कूलों में तीन भाषा फार्मूला लागू करने से इनकार कर दिया है जहां हिंदी तीसरी भाषा है। तमिलनाडु ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के हिस्से के रूप में तीन भाषा फार्मूले को लागू करने से साफ इनकार कर दिया है। राज्य इसे पिछले दरवाजे से हिंदी और संस्कृत लाने का प्रयास बताता है।

भाजपा को छोड़कर तमिलनाडु के सभी राजनीतिक दलों ने एनईपी के क्रियान्वयन का विरोध किया है। इनमें भाजपा के सहयोगी दल पट्टाली मक्कल काची और देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कझगम शामिल हैं। उनका कहना है कि यह राज्य की स्वायत्तता का उल्लंघन है।

जो लोग शासन करने के लिए विभाजन करते हैं, वे अंततः विभाजित लोगों को एकजुट करने में सफल होते हैं, जिसकी उन्हें खुद को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। भारत के इतिहास में विस्तार चाहने वालों के ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं, जो अंततः अपने पदचिह्नों को सिकोड़कर गुमनामी में खो देते हैं।

****

राणा सांगा: 500 साल पुराने इतिहास पर टकराव क्यों?

~प्रो प्रदीप माथुर

प्रो. प्रदीप माथुर

संसद के एक वरिष्ठ सदस्य के एक साधारण से बयान ने एक बड़े विवाद को जन्म दे दिया है, जिससे टकराव की नौबत आ गई है। सबसे बुरी बात यह है कि कुछ लोगों ने इस अनावश्यक विवाद का इस्तेमाल अपने राजनीतिक दलों के फायदे के लिए करने की कोशिश की है।

एक स्कूली छात्र के रूप में, मैंने अपनी इतिहास की किताब में पढ़ा कि राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था, और यह छह दशक से भी ज़्यादा पहले की बात है। मेरी कक्षा में सभी जातियों और समुदायों के छात्र थे। फिर, एक कॉलेज के छात्र के रूप में, मैंने आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज में पढ़ाई की, जिसे आज राजा बलवंत सिंह कॉलेज के नाम से जाना जाता है।

यह एक ऐसा कॉलेज है जो गर्वित क्षत्रियों द्वारा संचालित और वर्चस्व वाला है, जिनके परिवार तब भी एक भव्य सामंती व्यवस्था के सभी ढाँचे को धारण किए हुए थे जब मैं वहाँ एक छात्र था। हालाँकि, मैंने कभी किसी को राणा सांगा द्वारा किए गए कार्यों की परवाह करते या उनके कृत्य का बचाव करते नहीं सुना, जिसका इतिहास की किताबों में ज़िक्र तो है ही।

चाहे जो भी मकसद हो, यह इतिहास का एक तथ्य है कि राणा सांगा ने बाबर को दिल्ली पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया क्योंकि वह दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से हिसाब चुकता करना चाहता था और वह सैन्य रूप से इतना मजबूत नहीं था कि वह अकेले उससे

मुकाबला कर सके। शायद उसे उम्मीद थी कि बाबर मध्य एशिया में अपने राज्य में वापस लौट जाएगा, जो नहीं हुआ। बाकी मुगल इतिहास है।

राणा सांगा ने जो किया वह राजाओं और सुल्तानों के बीच एक आम बात थी जो हमेशा अपने राज्यों की सीमाओं को बढ़ाना चाहते थे ताकि अधिक प्रभाव और अधिक राजस्व संसाधन मिल सकें। यह कुछ वैसा ही था जैसा गठबंधन के राजनीतिक दल - बड़े और छोटे - आज चुनाव जीतने और सरकार बनाने के लिए करते हैं। रंगा सांगा निस्संदेह एक महान योद्धा और निडर योद्धा थे। उन्होंने जिस गठबंधन की मांग की, वह एक महान सेनापति और प्रशासक के रूप में उनकी क्षमता को नहीं दर्शाता है। वह एक महान देशभक्त भी थे, लेकिन उनका देश उनका राज्य था, न कि पूरा भारतीय उपमहाद्वीप। और 1947 में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत के विभाजन से पहले और 2014 के बाद, जब मोदी युग शुरू हुआ, हिंदू-मुस्लिम आधार पर किसी की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाया गया था। हिंदू राजाओं के पास मुस्लिम सेनापति और सैनिक थे, और मुस्लिम राजाओं और मुगल सम्राटों के पास हिंदू सेनापति और हिंदू सैनिक थे। मुगल सम्राट औरंगजेब, जिसे सबसे हिंदू विरोधी मुस्लिम शासक के रूप में चित्रित किया गया है, उसकी विशाल सेना का कमांडर-इन-चीफ एक हिंदू था।

इसलिए, पानीपत के प्रथम युद्ध के 500 साल बाद, जिसने भारत में मुगल वंश के लिए मार्ग प्रशस्त किया, एक मुसलमान को आमंत्रित करने के लिए राणा सांगा की

साख पर सवाल उठाना सरासर मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं है। यह इतिहास के ज्ञान के साथ-साथ उस समय के सामाजिक और राजनीतिक मैट्रिक्स की समझ की कमी को दर्शाता है।

सवाल यह है कि अगर इस मुद्दे पर विवाद तर्कहीन और मूर्खतापूर्ण है, तो यह इतना बड़ा टकराव क्यों बन गया है कि कानून-

व्यवस्था की स्थिति भी खतरे में पड़ गई है? इसका जवाब है करणी सेना के सदस्यों की भावनात्मक प्रतिक्रिया, जो राजस्थान के क्षत्रिय समुदाय के युवा सदस्यों का एक जातीय संगठन है, जो वर्ष 2006 में मूल रूप से सरकारी सेवा में नौकरियों की मांग को लेकर बना था।

आश्चर्य की बात है कि जब हमारी प्राथमिकताएं तेज़ सामाजिक-आर्थिक विकास के मुद्दे होने चाहिए, तब ऐसा महत्वहीन मुद्दा सामने आना स्वाभाविक है। क्या यह नहीं दर्शाता कि 21वीं सदी की दुनिया में रहने के लिए उपयुक्त आधुनिक समाज के रूप में हमारे विकास में कुछ गड़बड़ है?

सच तो यह है कि अब हम ऐसे लोगों का देश बन गए हैं जो हमेशा तनाव में रहते हैं और जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। हमने अपना सेंस ऑफ ह्यूमर खो दिया है। खुद पर हंसने की क्षमता अब पुरानी बात हो गई है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तब हमारे पास सेंस ऑफ ह्यूमर कैसे हो सकता था और अब जब मैं किशोर बच्चों का दादा हूँ, तो हमारे पास सेंस ऑफ ह्यूमर क्यों नहीं हो सकता? हास्य के खत्म होने के साथ ही, हम अपनी प्रिय बातों के विपरीत किसी राय को बर्दाश्त करने की सहनशीलता और धैर्य भी खो चुके हैं। असहिष्णुता, धैर्य की कमी और आक्रामकता कमजोरी के लक्षण हैं।

यद्यपि हमारे पास एक संविधान है जो लोकतांत्रिक समाज के उदार मूल्यों का समर्थन और संरक्षण करता है, लेकिन कोई भी बात किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है, और एफआईआर दर्ज की जा सकती है तथा अदालती मामला शुरू किया जा सकता है।

हमारी विकास रणनीतियों में चाहे जितनी भी विसंगतियां और कमियां हों, लेकिन सच्चाई यही है कि आज हम आर्थिक मोर्चे पर चार-पांच दशक पहले की तुलना में कहीं बेहतर स्थिति में हैं। एक ऐसी अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति के साथ जो राष्ट्रों के समूह में पांच सबसे बड़ी और सर्वश्रेष्ठ में से एक है, हम कमजोरों का देश क्यों बन गए हैं? यह कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है और हमें इसके बारे में कुछ नहीं करना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।

कारण स्पष्ट है। हम उन मूल्यों को भूल चुके हैं जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पैदा हुए थे। वसुधैव कुटुंबम की हमारी बातें खोखली हैं। दुनिया की तो बात ही क्या करें, हम अपने पड़ोसियों और अपने नागरिकों को भी एक परिवार नहीं मानते। हम अब राष्ट्रीय एकता पर उचित जोर नहीं देते। बल्कि एकता के नाम पर हमने राष्ट्रवाद की अवधारणा को आगे बढ़ाया है, जो बिना किसी वैध कारण के अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यक समुदाय के उन लोगों की निष्ठा पर सवाल उठाता है जो कहते हैं कि यह गलत है और इसे रोका जाना चाहिए।

पिछले दशक में हमने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया है। हम यह भूल गए हैं कि एक बड़े और विविधतापूर्ण समाज में विभाजन की प्रवृत्ति कोई बाधा नहीं होती। विभाजन केवल हिंदू-मुस्लिम आधार पर नहीं हो सकता। यह प्रवृत्ति कई संस्कृतियों और भाषाओं वाले जाति-आधारित हिंदू समाज को भी विभाजित करेगी। राणा सांगा के साथ टकराव इसका एक उदाहरण मात्र है। हम पहले से ही महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में जाति/सांस्कृतिक संघर्ष देख रहे हैं।

अब समय आ गया है कि हम इन विभाजनकारी प्रवृत्तियों के खिलाफ दृढ़ता से काम करें और सांप्रदायिक सद्भाव तथा उन मूल्यों के मार्ग पर लौटें, जिन्हें हमने महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रचारित भारत के विचार के साथ आत्मसात किया था।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार , मीडिया गुरु एवं मीडिया मैप के संपादक हैं।

भारतीय राजनीति में वामपंथियों के लिए निर्णायक समय

~धर्मेंद्र आज़ाद

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन, भारत, यूरोपीय संघ और मैक्सिको समेत कई देशों से आयातित वस्तुओं पर एकतरफा और कठोर टैरिफ लगाए जाने के बाद वैश्विक पूंजीवादी-साम्राज्यवादी व्यवस्था- जो पहले से ही अपने आंतरिक अंतर्विरोधों के कारण चरमरा रही थी-अब खुले टकराव के दौर में प्रवेश कर गई है। यह केवल एक नियमित व्यापार नीति नहीं है, बल्कि यह पूंजीवादी-साम्राज्यवादी व्यवस्था के भीतर गहराते संकट की तीव्र अभिव्यक्ति है, जो न तो अपने लाभ की दर को बनाए रख सकता है और न ही जनता को स्थिरता, रोजगार या उम्मीद प्रदान कर सकता है।

ट्रम्प की टैरिफ नीति साम्राज्यवादी मानसिकता की नवीनतम अभिव्यक्ति है, जो हर संकट को राष्ट्रवाद, संरक्षणवाद और सैन्यीकरण के पर्दे के पीछे छिपाती है, जबकि वास्तव में पूंजी के हितों की रक्षा करती है।

इस टैरिफ युद्ध के जवाब में, चीन ने 34% तक टैरिफ लगाया और अमेरिका को दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे अमेरिकी तकनीक और रक्षा उद्योग की आपूर्ति श्रृंखला को बड़ा झटका लगा। यूरोपीय संघ ने WTO से शिकायत की और रूस ने ट्रम्प को "वैश्विक व्यापार अपहरणकर्ता" तक कहा। 7 अप्रैल, 2025 को अमेरिका, यूरोप और एशिया के शेयर बाजारों में 4% से 7% तक की गिरावट देखी गई। IMF और विश्व बैंक ने मंदी की संभावना 64% आंकी है, जो इस प्रणाली की सड़ी हुई नींव का संकेत है।

> डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों ने वैश्विक पूंजीवादी-साम्राज्यवादी व्यवस्था को खुली टकराव की स्थिति में धकेल दिया है। यह लेख दर्शाता है कि कैसे यह आर्थिक संकट वैश्विक सत्ता ढांचे की गहराई से हो रही दरारों और आंतरिक अंतर्विरोधों का परिणाम है। अमेरिका से लेकर भारत तक, इस संकट ने न केवल आर्थिक अस्थिरता बल्कि सामाजिक विद्रोहों और वैचारिक पुनर्जागरण को जन्म दिया है। IMF की चेतावनी, बाजारों की गिरावट और विरोध आंदोलनों का उभार इस पूंजीवादी व्यवस्था के पतन की आहट है।

हालाँकि, यह संकट सिर्फ़ आर्थिक संकट से कहीं ज़्यादा है - इसने सामाजिक अशांति और वैचारिक विस्फोटों को जन्म दिया है। अमेरिका में, "हैंड्स ऑफ़!" नामक एक आंदोलन उभरा है, जिसमें मज़दूर संघ, LGBTQIA+ समुदाय, नस्लीय न्याय संगठन, पर्यावरण कार्यकर्ता, वरिष्ठ अधिकार समूह और क्रांतिकारी वामपंथी ताकतें शामिल हैं। यह आंदोलन ट्रम्प की सामाजिक सुरक्षा कटौती, सत्ता पर एलन मस्क जैसे अरबपतियों की पकड़, सैन्यीकरण और पूंजीवादी लोकतंत्र के क्षरण के खिलाफ़ एक लोकप्रिय प्रतिरोध बन गया है।

हालांकि यह आंदोलन अभी व्यवस्था परिवर्तन या समाजवाद की सीधी मांग नहीं करता, लेकिन इसकी उभरती वर्ग चेतना और विरोध की दिशा यह संकेत देती है कि जनता का असंतोष अब सुधारवाद की सीमाओं से आगे बढ़ रहा है। पेरिस, बर्लिन, लंदन और टोरंटो जैसे शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों ने इसे वैश्विक चेतना

में बदल दिया है - एक पुनर्जागरण जिसमें व्यवस्था परिवर्तन का दर्द पोषित किया जा रहा है।

भारत में भी संकट बहुत गहरा है। नोटबंदी, जीएसटी, महामारी और कॉरपोरेट हितैषी नीतियों के कारण पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था अब टैरिफ युद्ध के प्रतिकूल प्रभावों से और भी अधिक प्रभावित हो रही है। अमेरिका द्वारा फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल और आईटी क्षेत्रों पर टैरिफ लगाए जाने से भारत के निर्यात में गिरावट आ रही है। एमएसएमई क्षेत्र, जो भारत के कुल रोजगार का 30% और इसके निर्यात का 45% हिस्सा है, अब दोहरे हमले का सामना कर रहा है: एक वैश्विक टैरिफ युद्ध से और दूसरा केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों से।

सेंसेक्स में गिरावट, उपभोक्ता मांग में ठहराव, रुपये में ऐतिहासिक गिरावट और बेरोजगारी दर का 9% को पार करना, ये सभी संकेत हैं कि भारत की पूंजीवादी व्यवस्था अब अपने वजन के नीचे ढह रही है। इसके बावजूद, सरकार "व्यापार करने में आसानी" की आड़ में श्रम अधिकारों को कमजोर कर रही है, सार्वजनिक संस्थानों को निजी पूंजी के हवाले कर रही है और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे कल्याणकारी क्षेत्रों को लाभ-संचालित बाजार में धकेल रही है।

यह वह ऐतिहासिक काल है जब पूंजीवाद अपने आंतरिक अंतर्विरोधों के कारण खुद को निगलने लगता है और फासीवाद जन असंतोष को राष्ट्रवादी और सांप्रदायिक हिंसा में बदल देता है।

पूंजीवाद अपने आंतरिक अंतर्विरोधों के कारण खुद को निगलने लगता है और फासीवाद जन असंतोष को राष्ट्रवादी और सांप्रदायिक हिंसा में बदल देता है। यह वह क्षण है जब आंदोलनों को अब आर्थिक और कानूनी संघर्षों तक सीमित नहीं रहना चाहिए

यह वह क्षण है जब आंदोलनों को अब आर्थिक और कानूनी संघर्षों तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि वर्ग संघर्ष की दिशा में संगठित होना चाहिए।

भारत के क्रांतिकारी वामपंथी आंदोलनों के लिए यह निर्णायक समय है। गांवों, झुग्गी-झोपड़ियों, औद्योगिक क्षेत्रों और विश्वविद्यालयों में वर्ग चेतना को संगठित करना अब जरूरी है। हर लोकप्रिय आंदोलन - चाहे वह महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण, लैंगिक भेदभाव, जाति-आधारित उत्पीड़न या धार्मिक ध्रुवीकरण के खिलाफ हो - को समाजवादी दिशा और रणनीति से जोड़ा जाना चाहिए।

अब जरूरत है उत्पादन के समाजवादी संबंधों के विचार को साकार करने की - जहां उत्पादन लाभ के लिए नहीं, बल्कि मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए हो; जहां संसाधनों का न्यायोचित पुनर्वितरण हो; और जहां सत्ता की बागडोर एक श्रमिक लोकतांत्रिक पार्टी के हाथ में हो, जो व्यवस्था परिवर्तन के संघर्ष से उभरी हो।

अगर हम इस ऐतिहासिक अवसर को पहचानने में विफल रहे, तो यह संकट तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का कारण बन सकता है। पूंजीवादी लोकतंत्र अपना मुखौटा उतार सकता है और फासीवाद अपने नग्न रूप में सामने आ सकता है।

इतिहास दरवाज़े पर दस्तक दे रहा है। समय सीमित है या तो हम इस व्यवस्था को बदल दें, या यह व्यवस्था हमें इतिहास से मिटा देगी।

वक्फ बिल पर एक मुस्लिम महिला का अनुभव

~एन. सत्यामूर्ति

एन सत्या मूर्ति

वक्फ विधेयक के चलते उपजे विवाद से पहले ही दक्षिणी तमिलनाडु में एक हिंदू नेता ने राज्य के एचआर एंड सीई विभाग पर एक मुस्लिम महिला, नरगिस खान, को मंदिर ट्रस्टी नियुक्त करने का आरोप लगाकर विवाद छेड़ दिया था। बाद में पता चला कि वह महिला हिंदू थी, और उसका नाम एक मुस्लिम डॉक्टर के सम्मान में रखा गया था, जिसने उसकी माँ की डिलीवरी में मदद की थी। इस गलत आरोप के लिए हिंदू नेता को गिरफ्तार किया गया।

राज्यसभा में वक्फ विधेयक पर बहस के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरोप लगाया कि एक मंदिर शहर में 400 एकड़ ज़मीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया है और स्थानीय लोगों को लेन-देन के लिए वक्फ बोर्ड से NOC लेने को कहा गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी तिरुचेंदूर मुरुगन मंदिर की संपत्ति को लेकर ऐसे ही आरोप लगाए। राज्य सरकार ने इन आरोपों को 'राजनीतिक' कहकर खारिज कर दिया।

डीएमके का विरोध और सुप्रीम कोर्ट की तैयारी

तमिलनाडु विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से अपील की कि वह वक्फ विधेयक पारित न करे। मुख्यमंत्री एमके

स्टालिन ने कहा कि डीएमके इस विधेयक की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। हालांकि ओवैसी ने पहले ही याचिका दाखिल कर दी थी। डीएमके इस विधेयक के उस प्रावधान का विरोध कर रही है जिसमें गैर-मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड का सदस्य बनाने की बात कही गई है।

सवाल यह उठता है कि जब नरगिस खान को हिंदू मंदिर ट्रस्टी के तौर पर मंजूर नहीं किया गया, तो फिर वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम की नियुक्ति कैसे न्यायसंगत हो सकती है?

पारंपरिक सौहार्द का तमिल उदाहरण

तमिलनाडु में धार्मिक समुदायों के बीच ऐतिहासिक सौहार्द और मेलजोल का लंबा इतिहास रहा है। उदाहरण के लिए, मुस्लिम समुदाय हिंदू त्योहारों में भाग लेते हैं और सेवा प्रदान करते हैं। अर्काट के नवाब ने मायलापुर के श्री कपालेश्वर मंदिर को जमीन दी थी। इस्लाम का प्रवेश व्यापारियों के ज़रिए हुआ और इसे उत्तर भारत के आक्रामक प्रसार से अलग देखा जाता है।

यह सौहार्द, डीएमके और एआईएडीएमके के लिए गर्व का विषय है, जिसे वे वक्फ विधेयक जैसे मामलों के ज़रिए खतरे में पाते हैं।

सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव और विपक्ष की चुप्पी

विधानसभा में वक्फ विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें सिर्फ़ भाजपा के चार विधायकों ने वॉकआउट किया। एआईएडीएमके ने प्रस्ताव का समर्थन किया, भले ही वह भाजपा के साथ गठबंधन फिर से बहाल करने की सोच रही है। भाजपा विधायक खुले विरोध से बचते हुए वॉकआउट कर गए ताकि प्रस्ताव 'सर्वसम्मति से' पारित माना जाए।

यह इस बात का संकेत था कि तमिलनाडु में वक्फ विधेयक को लेकर ज़मीन पर भाजपा को कोई ठोस जनसमर्थन नहीं है।

भाजपा और एआईएडीएमके के बीच चुनावी अविश्वास

AIADMK कार्यकर्ताओं का मानना है कि 2019 और 2021 में पार्टी की हार का मुख्य कारण भाजपा के साथ अनुचित गठबंधन था। उन्हें लगता है कि दिवंगत जयललिता ने कभी भाजपा को स्वीकार नहीं किया होता, और अगर वह होतीं तो भाजपा के साथ गठबंधन न करतीं। हालांकि 2024 में भाजपा से अलग होने के बावजूद पार्टी को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, जिससे पार्टी के भीतर मतदाता अविश्वास की भावना और गहरी हुई।

डीएमके की विचारधारा मूलतः नास्तिक और हिंदू विरोधी रही है। पिछले कुछ समय से पार्टी ने 'मध्य-मार्ग' अपनाया था, लेकिन अब केंद्र की हिंदुत्व उकसाने वाली नीतियों के चलते पार्टी ने फिर से अपने मूल विचारों की ओर रुख करना शुरू किया है। इससे पार्टी को अपने अल्पसंख्यक वोट बैंक को मज़बूत करने में मदद मिल सकती है।

कुछ कार्यकर्ताओं का मानना है कि अगर AIADMK को सरकार बनाने के लिए समर्थन चाहिए होगा, तो भी वे भाजपा से समर्थन नहीं लेंगे।

डीएमके का वैचारिक पक्ष

डीएमके की विचारधारा मूलतः नास्तिक और हिंदू विरोधी रही है। पिछले कुछ समय से पार्टी ने 'मध्य-मार्ग' अपनाया था, लेकिन अब केंद्र की हिंदुत्व उकसाने वाली नीतियों के चलते पार्टी ने फिर से अपने मूल विचारों की ओर रुख करना शुरू किया है। इससे पार्टी को अपने अल्पसंख्यक वोट बैंक को मज़बूत करने में मदद मिल सकती है।

डीएमके को यह भी लगता है कि 'ऑनलाइन हिंदुत्व' के ज़रिए नए युवाओं को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, जिससे उनकी मूल विचारधारा को चुनौती मिल रही है।

तमिलनाडु की सामाजिक मानसिकता

तमिल समाज की विडंबना यह है कि राज्य के हिंदू गहराई से धार्मिक होते हुए भी अपनी धार्मिक पहचान को राजनीति से नहीं जोड़ते। एक आम तमिल हिंदू सुबह मंदिर जाकर पूजा करेगा और फिर मतदान केंद्र जाकर डीएमके को वोट देगा। यही भाजपा और आरएसएस की रणनीति के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।

राज्य की सामाजिक संरचना इतनी जटिल है कि यहाँ हिंदुत्व की सीधी राजनीति कारगर नहीं हो पाती। भाजपा और आरएसएस तमिल मानसिकता को बदलने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन उन्हें अब तक सफलता नहीं मिली है।

भारत की विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह में मंदी की आशंका

~प्रो शिवाजी सरकार

प्रो शिवाजी सरकार

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के विश्व आर्थिक परिदृश्य (डब्ल्यूईओ) के अनुसार, अमेरिकी टैरिफ युद्ध, जिसने 80 वर्षों से विश्व व्यवस्था को पुनर्निर्धारित कर रखा है, 2025 में वैश्विक विकास दर को धीमा करके 2.8 प्रतिशत कर देगा, जो जनवरी के पूर्वानुमान 3.3 प्रतिशत से कम है।

आईएमएफ का पूर्वानुमान गंभीर है क्योंकि उसे महामंदी (जीडी) की पुनरावृत्ति या उससे भी बदतर स्थिति का अनुमान है, क्योंकि अमेरिका की प्रभावी टैरिफ दर जीडी के दौरान पहुँचे स्तरों से आगे निकल गई है, जबकि प्रमुख व्यापारिक साझेदारों की जवाबी प्रतिक्रियाओं ने वैश्विक दर को काफी हद तक बढ़ा दिया है। दुनिया में उथल-पुथल मच सकती है क्योंकि अमेरिका गंभीर मंदी में जा सकता है और इसकी वृद्धि दर 1.8 प्रतिशत तक गिर सकती है, जो 90 आधार अंकों की गिरावट है। समस्याएँ आर्थिक संकट से बढ़कर व्यापार तनाव को और बदतर कर सकती हैं, जो एक बड़े राजनीतिक संघर्ष की ओर इशारा करता है।

उम्मीद की किरण - भारत की वृद्धि दर 6.2 प्रतिशत रहने वाली है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमानों के अनुरूप है, हालांकि चीन की वृद्धि दर में गिरावट आने की संभावना है, क्योंकि जनवरी 2025 के WEO पूर्वानुमान में इसकी जीडीपी वृद्धि दर 4.6 प्रतिशत से घटकर 4 प्रतिशत रह गई है। हालांकि, भारत के लिए वृद्धि का परिदृश्य अपेक्षाकृत अधिक स्थिर है। आईएमएफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए स्थिर विस्तार का अनुमान लगाया है, जिसे निजी खपत, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत समर्थन प्राप्त है। अनिश्चितता और धीमी वृद्धि से चिह्नित वैश्विक वातावरण में, भारत की लचीलापन अलग से दिखाई देती है, जो वैश्विक आर्थिक गतिविधि के प्रमुख चालक के रूप में इसकी भूमिका को मजबूत करती है।

इन संशोधनों के बावजूद, भारत की मजबूत विकास दर वैश्विक मंच पर इसे अलग पहचान दिलाती है। अनुमान वैश्विक निवेश पैटर्न को बदल सकते हैं। देश के शेयर बाजारों में पूंजी पलायन, डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट और सोने और चांदी की कीमतों में उछाल के बावजूद यह भारत के लिए अतिरिक्त रुचि पैदा कर सकता है। WEO का कहना है कि डॉलर के और मजबूत होने से टैरिफ लगाने वाले देश के रूप में अमेरिका को लाभ होगा, इसलिए रुपया और गिर सकता है। इसके अलावा वैश्विक निवेश परिदृश्य में मुश्किलें आ सकती हैं, जिससे भारतीय बाजार में समस्याएं बढ़ सकती हैं।

हालांकि, नीतिगत अनिश्चितता, अमेरिका में विकास की कम संभावनाएं और डॉलर परिसंपत्तियों की वैश्विक मांग में समायोजन - जो अब तक व्यवस्थित रहा है - डॉलर पर दबाव डाल सकता है।

मध्यम अवधि में, यदि टैरिफ अमेरिकी व्यापार योग्य वस्तुओं के क्षेत्र में अपने व्यापारिक भागीदारों के सापेक्ष कम उत्पादकता में तब्दील हो जाते हैं, तो डॉलर का मूल्यह्रास हो सकता है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम बढ़ गए हैं, और बिगड़ते व्यापार तनाव से विकास में और गिरावट आ सकती है। वित्तीय स्थितियाँ और भी कठिन हो सकती हैं क्योंकि बाजार कम होते विकास की संभावनाओं और बढ़ती अनिश्चितता पर नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं। जबकि बैंक कुल मिलाकर अच्छी तरह से पूंजीकृत हैं, वित्तीय बाजारों को और अधिक कठिन परीक्षणों का सामना करना पड़ सकता है।

टैरिफ़ नकारात्मक आपूर्ति आघात का कारण बनते हैं जिससे उत्पादकता में कमी आती है और उत्पादन की कीमतें बढ़ती हैं, किराया मांग बढ़ती है - भ्रष्टाचार के लिए एक शब्द, जो विश्व विकास को और प्रभावित कर सकता है। प्रतिस्पर्धा कम होने पर एकाधिकार बढ़ सकता है।

अमेरिका में, हाल ही में नीतिगत घोषणाओं से पहले ही मांग में कमी आ रही थी, जो कि नीतिगत अनिश्चितता को दर्शाता है। मुद्रास्फीति में पहले से अनुमानित 2 प्रतिशत से एक प्रतिशत की वृद्धि के साथ, यह वैश्विक कीमतों में वृद्धि को बढ़ावा दे सकता है।

यूरो क्षेत्र में वृद्धि, जो अपेक्षाकृत कम प्रभावी टैरिफ के अधीन है, को 0.2 प्रतिशत अंक घटाकर 0.8 प्रतिशत कर दिया गया है। यूरो क्षेत्र और चीन दोनों में, मजबूत राजकोषीय प्रोत्साहन इस वर्ष और अगले वर्ष कुछ सहायता प्रदान करेगा। टैरिफ के निपटान के आधार पर कई उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं को महत्वपूर्ण मंदी का सामना करना पड़ सकता है। WEO ने समूह के लिए अपने विकास पूर्वानुमान को 0.5 प्रतिशत अंक घटाकर 3.7 प्रतिशत कर दिया है।

अनिश्चितता बढ़ी, तेल की कीमतें नरम हुईं

WEO का कहना है कि घनी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला टैरिफ और अनिश्चितता के प्रभावों को बढ़ा सकती है। अधिकांश व्यापारिक सामान मध्यवर्ती इनपुट होते हैं जो अंतिम उत्पाद में बदलने से पहले कई बार सीमाओं को पार करते हैं। व्यवधान वैश्विक इनपुट-आउटपुट नेटवर्क में ऊपर और नीचे फैल सकते हैं, जिसका संभावित रूप से बड़ा गुणक प्रभाव हो सकता है, जैसा कि हमने महामारी के दौरान देखा। अनिश्चित बाजार पहुंच का सामना करने वाली कंपनियां निकट भविष्य में रुक सकती हैं, निवेश कम कर सकती हैं और खर्च में कटौती कर सकती हैं। इसी तरह, वित्तीय संस्थान उधारकर्ताओं के जोखिम का पुनर्मूल्यांकन करेंगे। बढ़ती अनिश्चितता और वित्तीय स्थितियों में कसावट अल्पावधि में हावी हो सकती है, जिसका असर आर्थिक गतिविधियों पर पड़ सकता है, जैसा कि तेल की कीमतों में तेज गिरावट में परिलक्षित होता है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम बढ़ गए हैं, और बिगड़ते व्यापार तनाव से विकास में और गिरावट आ सकती है। वित्तीय स्थितियाँ और भी कठिन हो सकती हैं क्योंकि बाजार कम होते विकास की संभावनाओं और बढ़ती अनिश्चितता पर नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं। जबकि बैंक कुल मिलाकर अच्छी तरह से पूंजीकृत हैं, वित्तीय बाजारों को और अधिक कठिन परीक्षणों का सामना करना पड़ सकता है।

टैरिफ के निपटान के आधार पर कई उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं को महत्वपूर्ण मंदी का सामना करना पड़ सकता है। WEO ने समूह के लिए अपने विकास पूर्वानुमान को 0.5 प्रतिशत अंक घटाकर 3.7 प्रतिशत कर दिया है।

"हालांकि, अगर देश अपनी मौजूदा व्यापार नीति के रुख को नरम करते हैं और नए व्यापार समझौते करते हैं, तो विकास की संभावनाएं तुरंत बेहतर हो सकती हैं"। घरेलू असंतुलन को संबोधित करने से, वर्षों में, आर्थिक जोखिमों की भरपाई हो सकती है और वैश्विक उत्पादन बढ़ सकता है, जबकि बाहरी असंतुलन को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है।

किसान पहचान योजना : कृषि सुधार की दिशा में ऐतिहासिक कदम

~प्रो शिवाजी सरकार

प्रो शिवाजी सरकार

सम्राट अकबर के अधीन टोडरमल के प्रसिद्ध भूमि सुधारों की महत्वाकांक्षा को प्रतिध्वनित करते हुए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, भारत सरकार ने एक परिवर्तनकारी किसान पहचान योजना शुरू की है। यह सुधार भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम है। किसानों को एक मजबूत डिजिटल पहचान प्रदान करके, इस पहल का उद्देश्य पहुंच, पारदर्शिता और वित्तीय समावेशन के आसपास लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों से निपटना है, जिससे तकनीक-संचालित कृषि क्रांति की शुरुआत होगी।

अपने व्यापक लाभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल कार्यान्वयन के साथ, किसान आईडी में भारत में ग्रामीण सशक्तिकरण और सतत कृषि विकास की आधारशिला बनने की क्षमता है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत, पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को प्रति वर्ष ₹6,000 का प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ मिलता है। किसान आईडी का उपयोग इन किसानों की पहचान करने के लिए किया जाता है और यह सुनिश्चित करता है कि भुगतान सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में किया जाए। इस कदम से प्रशासनिक खर्चों में भारी कमी आने की उम्मीद है।

टोडरमल के भूमि सुधारों को भूमि की माप, स्थानों, आकारों और अन्य बुनियादी आंकड़ों की पहचान करने के लिए सबसे व्यापक सुधारों में से एक माना जाता है। व्यक्तिगत भूमि मालिकों को पहला लिखित पट्टा अवध और आगरा के सूबों में सटीकता के साथ जारी किया गया था - जो

वर्तमान उत्तर प्रदेश है। हालाँकि इसे एक सार्वभौमिक प्रणाली के रूप में देखा गया था, लेकिन यह बिहार और मुगल राजधानी से दूर अन्य क्षेत्रों में लड़खड़ा गई। बिहार में, पूरे गाँव को सामूहिक पट्टा जारी किया गया था, जिसके कारण लगातार विवाद होते रहे हैं। आज भी, बिहार में भूमि से संबंधित विवादों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की जाती है - एक ऐसा मुद्दा जिसकी नई डिजिटल प्रणाली के हिस्से के रूप में जांच की जानी चाहिए।

अब तक इस योजना ने लगभग 7 करोड़ भूमिधारक किसानों को डिजिटल पहचान प्रदान की है, जो अनुमानित 26.3 करोड़ कुल किसानों में से हैं। केवल उन्हीं लोगों को नामांकित किया जा रहा है जिनके पास ज़मीन है। हालाँकि, कृषि कहीं अधिक जटिल है, और इसमें शामिल सभी लोगों - किरायेदार, बटाईदार, कृषि मज़दूर - की पहचान करना एक चुनौती बनी हुई है।

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात पर जोर दिया है कि यह योजना समय पर वित्तीय सहायता सुनिश्चित करती है, तथा नियमित रूप से भुगतान किया जाता है। आधार से जुड़ी बैंक खाता प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि लाभ सीधे हस्तांतरित हो, जिससे प्रक्रिया सरल और सुरक्षित हो जाती है। प्रत्येक पंजीकृत किसान को एक डिजिटल किसान आईडी प्राप्त होती है, जिसमें उनका व्यक्तिगत और कृषि डेटा एक केंद्रीकृत डेटाबेस में सुरक्षित रूप से संग्रहीत होता है।

सरकार का कहना है कि किसान आईडी प्रत्येक किसान के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या के रूप में कार्य करती है, जिससे उन्हें लक्षित समर्थन प्राप्त करने में मदद मिलती है और पहले पहुंच से बाहर कई अवसर खुलते हैं। एक नंबर से कहीं अधिक, किसान आईडी ग्रामीण भारत में वित्तीय सहायता, तकनीकी सहायता और कुशल सरकारी सेवा वितरण का प्रवेश द्वार बनने के लिए तैयार है। सरकार का कहना है कि यह आईडी सुनिश्चित करती है कि किसान सीधे कृषि ऋण, फसल बीमा, इनपुट सब्सिडी और अन्य सरकारी

योजनाओं तक पहुंच सकते हैं, जिससे बिचौलियों की आवश्यकता कम हो जाती है और देरी कम से कम होती है। किसानों को दस्तावेजों के प्रमाणीकरण के लिए पटवारियों और अन्य भूमि या जिला अधिकारियों के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके जमीन के रिकॉर्ड अन्य वित्तीय विवरणों के साथ डिजिटल रूप से अपलोड किए जा रहे हैं। किसानों को अब दस्तावेजीकरण के लिए पटवारियों या जिला अधिकारियों के पास नहीं भागना पड़ता है, क्योंकि उनके जमीन के रिकॉर्ड और वित्तीय विवरण डिजिटल रूप से जुड़े हुए हैं

इसी तरह पीएम-किसान पेंशन योजना के तहत सालाना 6,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। फिर भी, कुछ आशंकाएँ बनी हुई हैं। आधार, पैन और अब भूमि रिकॉर्ड को जोड़ने से डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के बारे में चिंताएँ पैदा होती हैं। सरकार आश्वासन देती है कि पहुँच अनुमति आधारित है और डेटा सुरक्षित है, लेकिन आशंकाएँ बनी हुई हैं, खासकर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों को देखते हुए।

भूमि स्वामित्व मामले को और जटिल बनाता है। कई भूखंड संयुक्त रूप से स्वामित्व वाले होते हैं, कभी-कभी आंशिक हिस्से वाले कई लोगों के पास। यह स्पष्ट नहीं है कि इन्हें कैसे संभाला जाएगा - क्या संयुक्त आईडीएस होगा या अन्य तंत्र होंगे। इस बात पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है कि ऐसे मामलों के लिए पट्टों को कैसे डिजिटल किया जाएगा।

यहां तक कि किसानों की सही संख्या भी अनिश्चित बनी हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 26.3 करोड़ किसान थे - 11.8 करोड़ किसान और 14.4 करोड़ खेतिहर मजदूर। लेकिन कृषि जनगणना, एनएसएसओ और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण सहित सरकारी सर्वेक्षणों में परिभाषाएं अलग-अलग हैं। इसके अलावा, डेटा पुराना है। 2011 का एक प्रमुख अवलोकन कृषि में लगे कार्यबल के प्रतिशत में गिरावट थी, जो 2001 में 58.2 प्रतिशत से 2011 में 54.6 प्रतिशत हो गई। हाल ही में नाबार्ड के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 2016-17 और 2021-22 के बीच औसत भूमि जोत के आकार में 31 प्रतिशत की गिरावट आई है।

कृषि कार्यबल किसानों से मजदूरों में बदल रहा था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अनुसार, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि 50 लाख हेक्टेयर भूमि खेतों से सड़कों पर स्थानांतरित हो रही है। 2019 के बाद से इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव का अध्ययन किया जाना बाकी है।

ई-एनएएम पंजीकरण भी हैं। ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत किसानों की संख्या बढ़ रही है, जो आधुनिक बाजार प्रथाओं में भाग लेने वाले किसानों की बढ़ती संख्या को दर्शाता है। मार्च 2025 तक, लगभग 17 मिलियन किसान ई-एनएएम पर पंजीकृत थे, जिसमें उत्तर प्रदेश पंजीकरण संख्या में सबसे आगे था।

कृषि कार्यबल किसानों से मजदूरों में बदल रहा था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अनुसार, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि 50 लाख हेक्टेयर भूमि खेतों से सड़कों पर स्थानांतरित हो रही है। 2019 के बाद से इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव का अध्ययन किया जाना बाकी है।

भूमि स्वामित्व भी सरल नहीं है। कृषि जनगणना में कृषि के लिए इस्तेमाल की जाने वाली किसी भी भूमि को शामिल किया जाता है, भले ही उसका मालिकाना हक उस व्यक्ति के पास न हो। भारत में किसानों का एक बड़ा हिस्सा छोटे और सीमांत हैं, जिनके पास आम तौर पर दो हेक्टेयर से भी कम ज़मीन होती है।

2020-21 में, कृषि ने भारत के आधे से ज़्यादा कार्यबल को रोज़गार दिया और देश के सकल घरेलू उत्पाद में 20.2% का योगदान दिया। भारत खाद्यान्न, फल और सब्ज़ियाँ, चाय, खेती की गई मछली, कपास, गन्ना, गेहूँ और चावल का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। इनमें से कई में अलग-अलग कृषि पैटर्न हैं।

एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बटाईदारी या पट्टे पर खेती है। किसान पहचान पत्र में उन्हें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यह एक कमी हो सकती है।

इसके अलावा मछुआरे वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए मछली पकड़ने में लगे हुए हैं, जलीय कृषि या मछली किसान, और मनोरंजन/खेल मछुआरे। हालांकि गतिविधियाँ अलग-अलग हैं, लेकिन ओवरलैप भी हैं। इन श्रेणियों को कैसे सूचीबद्ध किया जाता है।

ब्रिटेन को मांगनी चाहिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए माफी

~प्रभजोत सिंह

प्रभजोत सिंह

जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए औपचारिक माफ़ी की मांग फिर से उठ खड़ी हुई है, ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने इस मुद्दे को उठाया है। पूर्व सांसद और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष तरलोचन सिंह ने ब्रिटिश सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी से हाउस ऑफ कॉमन्स में इस मांग का समर्थन करने का आग्रह किया है।

इसकी तुलना कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की 2016 में कोमागाटा मारू घटना के लिए माफ़ी से की जा रही है, जिसमें सैकड़ों भारतीय अप्रवासियों को कनाडा में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था और उन्हें हिंसक स्थिति में वापस भेज दिया गया था। ट्रूडो ने भेदभावपूर्ण कानूनों को लागू करने में कनाडा की भूमिका को स्वीकार किया और औपचारिक माफ़ी मांगी। हालाँकि, बार-बार माँग के बावजूद, ब्रिटेन ने अभी तक "खेद" व्यक्त करने से आगे नहीं बढ़ा है।

ऐतिहासिक संदर्भ

13 अप्रैल, 1919 को हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ब्रिगेडियर-जनरल रेजिनाल्ड डायर के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने अमृतसर में एकत्रित निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए और घायल हुए। यह हत्याकांड औपनिवेशिक उत्पीड़न का प्रतीक बन गया और इसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ़ प्रतिरोध को बढ़ावा दिया।

विचारणीय मुख्य मुद्दे

- **राजकीय आतंकवाद:** क्या यह नरसंहार नागरिकों के विरुद्ध राज्य प्रायोजित हिंसा का जन्म था?

शहीदों के लिए न्याय: क्या भारत ने अपने प्राण गंवाने वालों को सम्मान देने के लिए पर्याप्त कार्य किया है?

- **अनुष्ठान बनाम वास्तविक स्वीकृति:**

क्या मात्र समारोह पर्याप्त हैं, या औपचारिक क्षमायाचना आवश्यक है?

- **मीडिया की भूमिका:**

नरसंहार के दौरान और उसके बाद सेंसरशिप ने जनता की धारणा को किस प्रकार आकार दिया?

प्रेस की भूमिका

नरसंहार के बाद प्रेस की स्वतंत्रता पर बहुत अधिक प्रतिबंध लगा दिए गए थे। अंग्रेजों ने कठोर सेंसरशिप कानून लागू कर दिए थे और *द ट्रिब्यून* के तत्कालीन संपादक कालीनाथ रे को ब्रिटिश कथन का विरोध करने के लिए जेल में डाल दिया गया था। दमन के बावजूद, मीडिया ने ब्रिटिश अत्याचारों को उजागर करने और राष्ट्रवादी भावनाओं को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

एक भीषण नरसंहार जिसने इतिहास बदल दिया

जलियांवाला बाग शुरू में एक महत्वहीन जगह थी, लेकिन नरसंहार के बाद, यह औपनिवेशिक क्रूरता का प्रतीक बन गया। सभा में शामिल होने वाले कई लोग आसन्न रक्तपात से अनजान थे; कुछ लोग वैसाखी समारोह या पशु मेले के लिए आए थे। जनरल डायर को लगा कि भीड़ शत्रुतापूर्ण है, इसलिए उसने अपने सैनिकों को - जिसमें 25 गोरखा और 25 बलूची शामिल थे - बिना किसी चेतावनी के गोली चलाने का आदेश दिया। लगभग 1,650 राउंड फायर किए गए, स्थानीय रिपोर्टों से पता चलता है कि मरने वालों की संख्या 1,000 से अधिक थी, जो ब्रिटिश स्रोतों द्वारा बताए गए 359-379 के आंकड़े से कहीं अधिक थी।

> ब्रिटिश सरकार ने ऐतिहासिक रूप से इस नरसंहार को कम करके आंका है, इसे पूरी तरह से जनरल डायर की लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया है, न कि प्रणालीगत औपनिवेशिक उत्पीड़न को स्वीकार किया है।

इतिहासकार वीएन दत्ता ने रैली के मुख्य आयोजक हंस राज को संभावित सरकारी एजेंट बताया, जिसने भीड़ को तितर-बितर होने से रोका। कथित तौर पर उसने डायर को गोली चलाने का संकेत दिया और फिर गायब हो गया, बाद में उसे अंग्रेजों ने मेसोपोटामिया में स्थानांतरित कर दिया।

मान्यता की मांग

अपने ऐतिहासिक महत्व के बावजूद, जलियांवाला बाग और उसके शहीदों को पूरा न्याय नहीं मिला है। हाल ही में हुए जीर्णोद्धार ने भले ही इस जगह की शक्ल-सूरत को आधुनिक बना दिया हो, लेकिन इससे उन लोगों का दर्द नहीं मिटता जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। ब्रिटिश सरकार ने अभी तक बिना शर्त माफ़ी नहीं मांगी है, जो कनाडा की पिछली गलतियों को स्वीकार करने के बिल्कुल विपरीत है।

नरसंहार की शताब्दी के दौरान, भारतीय गणमान्य व्यक्तियों ने औपचारिक श्रद्धांजलि अर्पित की, लेकिन जान गंवाने वालों की सही संख्या अज्ञात है। कुछ इतिहासकारों का तर्क है कि यह नरसंहार न केवल औपनिवेशिक क्रूरता का एक कृत्य था, बल्कि बढ़ते स्वतंत्रता आंदोलन में भय पैदा करने के लिए एक जानबूझकर किया गया कदम था।

ब्रिटिश प्रतिक्रिया

ब्रिटिश सरकार ने ऐतिहासिक रूप से इस नरसंहार को कम करके आंका है, इसे पूरी तरह से जनरल डायर की लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया है, न कि प्रणालीगत औपनिवेशिक उत्पीड़न को स्वीकार किया है। कई लोग तर्क देते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ'डायर ने भी नरसंहार की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह घटना पंजाब के नेताओं डॉ. सैफुद्दीन किचलू और डॉ. सत्य पाल की गिरफ्तारी और पांच यूरोपीय लोगों की हत्या के बाद व्यापक हिंसा के बाद हुई थी। कुख्यात रॉलेट बिल, जिसने अंग्रेजों को बिना किसी मुकदमे के भारतीयों को गिरफ्तार करने और हिरासत में रखने की अनुमति दी, ने आक्रोश को और बढ़ा दिया।

ब्रिटेन ने इस हत्याकांड की निंदा की है, लेकिन उसने औपचारिक माफ़ी नहीं मांगी है। इसके विपरीत, दुनिया ने राज्य आतंकवाद को फिर से परिभाषित किया है, और जलियाँवाला बाग निर्दोष नागरिकों के खिलाफ सत्ता के क्रूर दुरुपयोग का एक ज्वलंत उदाहरण बना हुआ है।

माफ़ी मांगने की बढ़ती मांग

हर साल, ब्रिटेन से अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने की मांग करने वाली आवाजें तेज होती जा रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह नरसंहार दोषपूर्ण औपनिवेशिक नीति का परिणाम था, जबकि अन्य इसे आतंक का पूर्व नियोजित कृत्य मानते हैं। जनरल डायर की कार्रवाई का उद्देश्य "सबक सिखाना" था, यह सुनिश्चित करना कि पंजाब विद्रोह का केंद्र न बने। हालाँकि, उसकी क्रूरता ने स्वतंत्रता के संकल्प को और मजबूत किया, जिसने मोहनदास करमचंद गांधी जैसे व्यक्तित्वों को महात्मा गांधी में बदल दिया।

कई लोग तर्क देते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ'डायर ने भी नरसंहार की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह घटना पंजाब के नेताओं डॉ. सैफुद्दीन किचलू और डॉ. सत्य पाल की गिरफ्तारी और पांच यूरोपीय लोगों की हत्या के बाद व्यापक हिंसा के बाद हुई थी।

इतिहास 13 अप्रैल, 1919 की घटनाओं का न्याय कर रहा है, ब्रिटेन के सामने एक नैतिक और कूटनीतिक सवाल है: क्या उसे औपनिवेशिक इतिहास के सबसे क्रूर नरसंहारों में से एक के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए? माफ़ी मांगने से अतीत को बदला नहीं जा सकता, बल्कि यह ऐतिहासिक गलतियों को स्वीकार करने और मानवाधिकारों और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करने की दिशा में एक कदम होगा।

****

लेखक वरिष्ठ पत्रकार है , खेल कूद पत्रकार्ता में उनकी विशेष रूचि है। और उन्होंने साथ ओलिंपिक कवर किये है। खेल - कूद के साथ ही व्यापर , वित्ति , स्वास्थ , विमानन और सिख -पंजाब राजनीति के भी विशेषज्ञ माने जाते है।

पहलगाम त्रासदी : नफरत की तेज़ होती आंधी

~प्रो राम पुनियानी

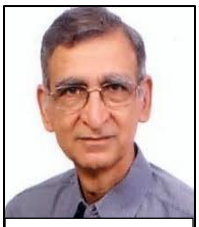
प्रो राम पुनियानी

पहलगाम के पास बैसरन में 26 पर्यटकों की हत्या हाल के समय की सबसे भीषण त्रासदियों में से एक है. बैसरन एक अत्यंत रमणीक स्थान है जहां सिर्फ घोड़े पर सवार होकर या ऊबड़-खाबड़ रास्ते पर पैदल चलकर पहुंचा जा सकता है.

इस हत्याकांड से सारा देश गहन शोक में डूब गया. यद्यपि आतंकवादियों ने पर्यटकों की हत्या उनके धर्म की पहचान करके की थी, लेकिन हमले का शिकार होने वालों में एक स्थानीय मुसलमान घोड़े वाला, जो पर्यटकों के साथ आया था, भी था. वह तब मारा गया जब उसने आतंकियों का विरोध किया. कश्मीरी कुलियों ने पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया और कश्मीरियों ने अपने घरों और मस्जिदों के दरवाजे मेहमानों के लिए खोल दिए. कश्मीर में बंद का आयोजन किया गया और 'हिंदू मुस्लिम एकता' का संदेश देने वाले कई जुलूस निकाले गए. सारे देश में मुसलमानों और अन्यों ने मोमबत्ती जुलूस निकाले और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की.

लगभग इन्हीं तारीखों में मोदीजी की कश्मीर यात्रा तय की गई थी. लेकिन निर्धारित तिथि के कुछ ही दिन पहले उसे रद्द कर दिया गया. घटना के समय वे सऊदी अरब में थे. घटना के बाद वे अपनी यात्रा अधूरी छोड़कर स्वदेश रवाना हो गए. किंतु

वापिस अपने के बाद कश्मीर जाने के बजाए वे एक चुनावी रैली में भाग लेने के लिए बिहार चले गए जहां उन्होंने आतंकियों को अंग्रेजी में कड़ी चेतावनी दी. आतंकी मुसलमान थे और मारे गए लोग हिंदू थे. इसे दबे-छिपे ढंग से इस घटना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बना दिया गया.

डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम की घोषणा की. मोदीजी ने इस बारे में कुछ अलग बात कही. इस बीच गोदी मीडिया की बन आई और उसने नफरत फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. वे अपने शानदार आरामदायक स्टूडियो में बैठे-बैठे पाकिस्तान के विभिन्न शहरों पर भारतीय सेना का कब्जा होने की खबरें देते रहे. गोदी मीडिया अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गया और उसने पत्रकारिता की आचार संहिता के उल्लंघन का नया रिकार्ड कायम किया, जिसे वह बहुत पहले ताक पर रख चुका है.

इस सबका सबसे बुरा नतीजा मुसलमानों के प्रति नफरत में बढ़ोत्तरी के रूप में सामने आया. सारा देश इस्लामोफोबिया के सैलाब में डूब गया और इसकी तीव्रता और स्तर अकल्पनीय ऊंचाई तक पहुंच गए. लातूर में एक

मुसलमान पर पाकिस्तानी होने का लेबिल चस्पा कर उसकी बुरी तरह पिटाई गई. उसे इतना अपमान महसूस हुआ कि उसने आत्महत्या कर ली. उत्तराखंड के एक हॉस्टल में कश्मीरी छात्रों को आधी रात को बाहर निकाल दिया गया और उन्हें देहरादून विमानतल के बाहर रात बितानी पड़ी. सबसे बुरी हरकत मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार के मंत्री विजय शाह ने की. उन्होंने भारतीय सेना की प्रवक्ता कर्नल सोफिया कुरैशी को 'आतंकवादियों की बहन' बताया. बाद में बात संभालने के लिए उन्होंने माफी मांग ली.

सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसायटी एंड सेक्यूलरिज्म, मुंबई की मिथिला राऊत ने दैनिक लोकसत्ता (मराठी) में प्रकाशित अपने एक लेख में विभिन्न समाचारपत्रों में छपी खबरों के आधार पर मुसलमानों के खिलाफ हुई नफरत-जनित हरकतों की जानकारी प्रस्तुत की है. उनके लेख के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद कई मुस्लिम विरोधी घटनाएं हुईं. ऐसी शर्मनाक घटनाओं में से एक उत्तरप्रदेश के शामली के ठोडा गांव में हुई जहां गोविंद ने सरफराज पर हमला किया. गोविंद ने कहा कि तुमने हमारे 26 मारे हम भी तुम्हारे 26 मारेंगे! पंजाब के डेरा बस्सी में यूनिवर्सल समूह के छात्रावास में कश्मीरी छात्रों पर हमला किया गया.

मसूरी में रहने वाले शब्बीर धर नाम के एक कश्मीरी, जो शाल बेचते थे, और उनके सहायक पर हमला किया गया और उन्हें पहलगाम की हत्याओं का कुसूरवार बताते हुए धमकाया गया कि यदि वे दुबारा वहां नजर आए तो बहुत बुरा होगा. हरियाणा के रोहतक नाम के गांव में मुस्लिम निवासियों को धमकाया गया और उनसे 2 मई तक गांव छोड़ देने के लिए कहा गया.

> बैसरन में 26 पर्यटकों की हत्या ने देश को झकझोर दिया। आतंकी हमले के बाद कश्मीर में जहाँ आम लोगों ने मानवता का परिचय दिया, वहीं देशभर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की बाढ़ आ गई। गोदी मीडिया और नफरती राजनीति ने हालात को और बिगाड़ा। यह घटना केवल आतंक की नहीं, बल्कि समाज में बढ़ती साम्प्रदायिकता की भी एक भयावह तस्वीर है।

ये तो केवल कुछ घटनाएं हैं जिनका विवरण समाचारपत्रों से पता लगा है. लेकिन इनसे यह साफ जाहिर है कि नफरत किस हद तक बढ़ गई है. समाज में माहौल धीरे-धीरे खराब हो रहा है. हिंदू दक्षिणपंथियों ने पहले से ही मुस्लिम विरोधी वातावरण बनाया हुआ है. शुरूआत में आरएसएस शाखाओं में मध्यकालीन इतिहास को तोड़-मरोड़ कर मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाई गयी. हाल के कुछ सालों में गोदी मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए मुसलमानों की शत्रु की छवि बनाई गई.

इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान के निर्माण से साम्प्रदायिक राजनीति करने वालों को एक नया हथियार मिल गया और उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान बनने के लिए मुसलमान जिम्मेदार हैं. यह पूरी तरह से इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश करने वाली बात थी क्योंकि पाकिस्तान के निर्माण की तीन वजहें थीं - अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, मुस्लिम साम्प्रदायिकता और हिन्दू साम्प्रदायिकता. द्विराष्ट्र सिद्धांत सबसे पहले हिन्दुत्ववादी विचारक विनायक दामोदर सावरकर ने पेश किया था.

पाकिस्तान बनने के बाद यह प्रोपेगेंडा कि पाकिस्तान के निर्माण के लिए मुसलमान जिम्मेदार हैं, नफरत फैलाने का एक नया औजार बन गया. हकीकत यह है कि दो देश, भारत और पाकिस्तान एक

साथ बने थे. मुस्लिम बहुल इलाके पाकिस्तान का हिस्सा बने. मुस्लिम-विरोधी प्रोपेगेंडा का एक नया मुद्दा बन गया कश्मीर का पेंचीदा मामला. 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों के कश्मीर से पलायन का इस्तेमाल भी मुसलमानों खिलाफ किया गया. जब यह पलायन हुआ था तब भाजपा समर्थित वी. पी. सिंह सरकार केन्द्र में सत्ता में थी और भाजपा की विचारधारा वाले जगमोहन कश्मीर के राज्यपाल थे. इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए मुसलमानों को पंडितों के पलायन की मुख्य वजह बताते हुए उनके प्रति घृणा को और बढ़ाया गया.

इस तरह एक के बाद एक कई मसलों का इस्तेमाल भारतीय मुसलमानों को सताने के लिए किया गया. इन दिनों भाईचारे की बातें बहुत कम सुनायी पढ़ती हैं और हर घटना का इस्तेमाल मुसलमानों के प्रति पहले व्याप्त नफरत को और बढ़ाने के लिए किया जाता है. इस नफरत का इस्तेमाल आरएसएस-भाजपा हिंदू राष्ट्र के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं.

पहलगाम के मसले से भारतीय कूटनीति की बदलती प्रकृति भी सामने आ गई है. 1972 में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुए शिमला समझौते के अनुसार सारे मसलों का समाधान किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के बिना द्विपक्षीय आधार पर ही किया जाना है. लेकिन अब तो पूरे मसले पर डोनाल्ड ट्रंप हावी हैं. नरेन्द्र मोदी उनका मुकाबला करने में अक्षम हैं. इससे समीकरण बदल गए हैं. वैश्विक स्तर पर ज्यादा देश भारत के पक्ष में खड़े नहीं हुए.

> पहलगाम के पास बैसरन में 26 निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया। इस भीषण वारदात के बाद जहां कश्मीरियों ने इंसानियत और एकता की मिसाल पेश की, वहीं देश के कई हिस्सों में मुसलमानों पर हमले और नफरत की घटनाएं सामने आईं। मीडिया और राजनीति ने इस त्रासदी को धार्मिक रंग देकर समाज को और बांटने का काम किया।

मुख्या मुद्दा यह है कि कश्मीर का मसला अटल बिहारी वाजपेयी के इंसानियत, कश्मीरियत और जम्हूरियत के नारे के आधार पर सुलझाया जाए. हम अपने पड़ोसियों के साथ शांति से रहें, यह बहुत जरूरी है. वाजपेयी ने ही कहा था कि "हम अपने मित्र तो चुन सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी नहीं चुन सकते". पाकिस्तान के प्रति दक्षिणपंथियां की नफरत और उसके साथ नफरती गोदी मीडिया की बकवास का नतीजा भारतीय मुसलमानों को भुगतना पड़ता है. इससे देश में सौहार्दपूर्ण माहौल कायम रखना मुश्किल हो जाता है.

पहलगाम के मसले के चलते और गहरी होती साम्प्रदायिकता की समस्या को समझने की जरूरत है और देश में शांति और समृद्धि के लिए नफरत और जंग की वकालत करने वालों को नकारना आवश्यक है. अब तक मुसलमानों को पाकिस्तानी कहकर गाली दी जाती थी अब उसमें कश्मीरी शब्द भी जुड़ गया है. इसका इस्तेमाल उनके प्रति नफरत बढ़ाने के लिए किया जा रहा है. (अंग्रेजी से रूपांतरण अमरीश हरदेनिया. लेखक आईआईटी मुंबई में पढ़ाते थे और सन 2007 के नेशनल कम्यूनल हार्मोनी एवार्ड से सम्मानित हैं)

नरेंद्र कुमार माथुर - एक नवोन्मेषी विचारक

एन.के. माथुर

बीएससी, बीएससी (इंजीनियरिंग), एमआईसीए, एफआईईटीई, आईटीएस (सेवानिवृत्त)

पूर्व विशेष सचिव एवं सलाहकार, दूरसंचार आयोग, भारत सरकार अध्यक्ष, इन्फोकॉम थिंक टैंक, नई दिल्ली

नरेंद्र कुमार माथुर एक नवोन्मेषी विचारक हैं, जिन्होंने भारत के दूरसंचार के क्षेत्र में क्रांति और परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका आदर्श वाक्य रहा है: देश की अपार संभावनाओं को साकार करने के लिए राष्ट्र की सेवा करना। वैदिक मंत्र लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु (विश्व में सभी लोग सुखी रहें) उनका मार्गदर्शक आदर्श वाक्य रहा है।

शिक्षा: बीएससी (राज. यूनिवर्सिटी) गोल्ड मेडलिस्ट, बीएससी इंजीनियरिंग (बीएचयू) मेरिट छात्रवृत्ति सभी 4 वर्ष, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंप्यूटर, वर्क स्टडी, नई तकनीक आदि पर इन-सर्विस सीनियर-लेवल कोर्स।

वर्तमान में: अध्यक्ष, इन्फोकॉम थिंक टैंक, नई दिल्ली-स्वायत्त वैज्ञानिक निकाय

पूर्व में:

• सलाहकार परिचालन, दूरसंचार आयोग/विशेष सचिव भारत सरकार (सेवानिवृत्त)-भारतीय दूरसंचार सेवा से 1990 में सेवानिवृत्त

• कुछ यूएनडीपी कार्यों पर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) के वरिष्ठ विशेषज्ञ; कुछ अवसरों पर संघ लोक सेवा आयोग के सलाहकार।

प्रबंधन के क्षेत्र में अनुभवी होने के कारण उन्होंने परिचालन स्तर के साथ-साथ नीति स्तर पर भी पहल की है। एनके माथुर दूरसंचार सेवाओं और सुविधाओं में भारत की प्रगति के लिए एक दर्जन से अधिक 'प्रथम' कार्यों के लिए जिम्मेदार रहे हैं।

• देश की पहली एसटीडी सेवा (1960 लखनऊ-कानपुर),

• ग्राहक सेवा केंद्रों की देशव्यापी श्रृंखला

• दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थानों का राष्ट्रीय नेटवर्क

• (तत्कालीन दुर्लभ) नई दूरसंचार सुविधाओं के लिए काउंटर पर पंजीकरण

• यूएन/आईटीयू सहयोग से राष्ट्रीय उन्नत-स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान के लिए परियोजना

• राष्ट्रव्यापी ट्रंक स्विचिंग के लिए नेटवर्क का मूल डिजाइन

• देश के पहले इलेक्ट्रॉनिक स्विच का प्रबंधन (1979 कोसी कलां)

• टेलीफोन की कमी के दिनों में, उन्होंने उत्तर प्रदेश को किसी भी स्थान पर टेलीफोन उपलब्ध कराने वाला पहला क्षेत्र बनाया: कोई भी 'अनुपयुक्त' क्षेत्र नहीं (1978)

• सार्वजनिक नेटवर्क पर डेटा संचार (1981-1982),

• 3 अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों (1982-83) के दौरान पूर्णतः दोषरहित संचार सेवाएं - एनएएम, एशियाड, चोगम - ने भारतीय दूरसंचार क्षमताओं को वैश्विक मानचित्र पर ला दिया, जिसकी सरकार और प्रधानमंत्री ने सराहना की।

• स्टाफ पुनर्गठन पर अंतर-विभागीय समिति के सदस्य-संयोजक, एसटीडी/आईएसडी सार्वजनिक टेलीफोन का देशव्यापी नेटवर्क (1988-1989),

• प्रथम दूरसंचार थिंक टैंक के संयोजक (2004-आईटीयू-एपीटी फाउंडेशन),

• कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों की नैतिकता पर देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी और कई अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए

डिजिटल कम्युनिकेशन इंडिया फोरम, पैसिफिक टेलीकम्युनिकेशंस कम्युनिटी (इंडिया) फाउंडेशन द्वारा भारतीय दूरसंचार उद्योग के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, 2021 से सम्मानित किया गया

उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व किया है और तकनीकी और प्रशासनिक मुद्दों पर रिपोर्ट, लेख और वार्ताएँ लिखी हैं। वे कई रणनीतिक मुद्दों पर निजी क्षेत्र के सलाहकार रहे हैं। उन्होंने अपने पूरे जीवन में सभी कार्यों में प्रभावकारिता और दक्षता लाने और नवाचार लाने के लिए अपने कौशल को समर्पित किया है और अपने आदर्श वाक्य और राष्ट्र को और मजबूत बनाने के लिए अपने अथक काम और प्रयासों में ऐसा करना जारी रखा है।

उनकी विविध रुचियाँ हैं और वे विकासात्मक गतिविधियों और सामाजिक मुद्दों पर स्थानीय समुदाय की सेवा करने में विशेष रुचि रखते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ होगा; पर्यावरण के मुद्दों पर उनके दृष्टिकोण को दिल्ली सरकार ने जल संरक्षण के क्षेत्र में 'जल रक्षक' प्रमाण पत्र देकर मान्यता दी है।

यूपी में कुछ स्थानों पर भूमि विभाजन के निपटारे के लिए पीएंडटी बोर्ड - साथ ही यूपी पोस्टल यूनिट के प्रमुख द्वारा उनकी सौहार्दपूर्ण और वस्तुनिष्ठ शैली की सराहना की गई। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार संस्थान और जिस कॉलोनी में वे रहते हैं, उसके रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा सम्मानित किया गया है। उनकी जीवनशैली हरिहरलाल श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई दो प्रेरणादायक पुस्तकों - हमारे प्रशासक (हमारे प्रशासक) और इन से सीखो (उनसे सीखें) में व्यक्त की गई है।

साधारण पृष्ठभूमि से उठकर, उनकी विनम्रता और दृढ़ता की उनसे बातचीत करने वाले सभी लोगों ने सराहना की है। उनकी विविध रुचियाँ हैं और वे विकासात्मक गतिविधियों और सामाजिक मुद्दों पर स्थानीय समुदाय की सेवा करने में विशेष रुचि रखते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ होगा; पर्यावरण के मुद्दों पर उनके दृष्टिकोण को दिल्ली सरकार ने जल संरक्षण के क्षेत्र में 'जल रक्षक' प्रमाण पत्र देकर मान्यता दी है। एक राष्ट्रवादी के रूप में, वे भारत को एक विश्व शक्ति के रूप में देखते हैं।

खतरे का अंत या मानवता की हार?

लेखक दिनेश वर्मा, भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी हैं। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने अपना समय लेखन को समर्पित किया और वर्ष 2016 में उनकी पहली किताब 'माई टाइम्स माई टेल्स' में प्रकाशित हुई जो 27 कहानियों का संग्रह है। पुस्तक का हिंदी अनुवाद "मेरे समय की मेरी कहानियाँ" के रूप में हुआ। प्रस्तुत कहानी उसी संग्रह से ली गयी है।

- संपादक

****

"इसे मारना नहीं चाहिए था। यह तो अपशगुन हो गया," उन्होंने मेरे कान में धीरे से तब फुसफुसाया जब एक घंटे का लगातार चलने वाला ड्रामा समाप्त हो चुका था। मैंने एक दम मुड़कर देखा। यह वही महिला थीं जो बराबर में रखी हुई ईटों के ढेर से ईटें उठा उठा कर उसे मारने के लिए मेरे हाथ में थमाती रहीं थीं।

एक शाम जब अंधेरा धीरे धीरे छाता जा रहा था, अपने कार्यालय से घर लौटकर मैंने मुँह हाथ धो कर कपड़े बदले और चाय पीने के लिए डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया और नाश्ता करते हुए दरवाज़े के पास दीवार के साथ की मेज़ पर रखे हुए टेली. विज़न पर न्यूज़ देखने लगा। मेरे फर्स्ट फ्लोर पर स्थित फ्लैट में डाइनिंग कम ड्राइंगरूम इस ढंग से बना हुआ था कि जहाँ मैं बैठा था वहाँ से टेलीविज़न देखते हुए दरवाज़े पर नज़र पड़ते रहना स्वाभाविक था।

क्योंकि मैं टेलीविज़न पर कार्यक्रम देख रहा था इसलिए दरवाज़े से आती हुई रोशनी को रोकने के लिए मैं ने अपनी बेटी से लकड़ी के दरवाज़े को बंद कर देने को कहा। लेकिन दरवाज़े तक पहुँचने से पहले ही वह घबरा कर झटके के साथ यह कहती हुई वापिस पलटी कि वहाँ सांप है। मेरी पत्नी ने उसे डांटते हुए स्वाभाविक रोष के साथ कहा, "सांप कहाँ से आ जाएगा। चूहा होगा। डरपोंक कहीं की।" "नहीं, वहाँ कुछ तो है," मैं ने कहा और मेरे यह कहते ही वहाँ अजीब सी शांति छा गई। क्योंकि मेरी दृष्टि दरवाज़े की दिशा में रखे हुए टेलीविज़न पर थी इसलिए मैंने भी किसी ऐसी चीज़ की झलक देखी थी जो अपने पतले शरीर को लोहे वाले दरवाज़े के नीचे से डाल कर अंदर घुसने का प्रयत्न कर रही थी। मैं बिल्ली की भांति बिना ध्वनि किए धीरे धीरे चलकर दरवाज़े के पास पहुँच गया और, अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, पास की कुर्सी पर चढ़कर दरवाज़े को झटके से खोल दिया। कुछ भी नहीं था। सामने का हिस्सा बिलकुल साफ पड़ा हुआ था। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास था कि मैं ने कुछ तो देखा था जो किसी सांप के शरीर के बीच के हिस्से जैसा मालूम पड़ रहा था क्योंकि उस पर वैसी ही धारियां पड़ी हुई थी।

मैंने अपनी पत्नी की इस बात को नकार दिया कि फर्स्ट फ्लोर पर आने के लिए सांप सीढ़ियाँ कैसे चढ़ेगा। उनका कहना था कि आखिर यह साफ सुथरी कॉलोनी थी और यहाँ सांप का फर्स्ट फ्लोर पर चढ़के आने की संभावना न के बराबर थी। वह यही कहे जा रही थी कि यदि कुछ था, तो कहाँ गायब हो गया। वाकई दूर दूर तक कहीं उसका निशान नहीं था। लेकिन कुछ तो था मुझे इस बारे में कोई शक नहीं था। मैंने जीवन में बहुत से सांप देखे थे और ज़हरीले साँपों की अनेको कहानियाँ भी सुनी थी। इसलिए मेरी आँखों को धोखा हुआ हो इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता। दो बार मैं सांप के चंगुल से अपनी जान बचा के निकला था यह बताने के लिए ही शायद कि मैं आज भी जिन्दा हूँ। एक बार देर रात्रि में पढ़ते पढ़ते मुझे प्यास लगी और मैं पानी पीने के लिए आंगन में स्थित चौके के दरवाज़े पर जा पहुँचा ताकि वहाँ से गिलास उठा लूं। मैं ने बिना नीचे देखे अंदर जाने के लिए एक पैर आगे बढ़ाया ही था कि पीले रंग की धारियों वाले सांप पर मेरी नज़र पड़ गई जो दरवाज़े को घेरे हुए लम्बा लम्बा पड़ा हुआ था। वह तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने अभी अपने पूर्ण शरीर को अंदर नहीं किया था और शरीर को वापिस कर पाने की स्थिति में था। लिहाजा सांप पर दृष्टि पड़ते ही किसी अच्छे खिलाड़ी की

तरह मैं तेजी से पीछे लौटा और भाग के अपने ताऊजी को जगा कर उन के साथ जब उसे देखने वहाँ वापस आया तो देखा कि वह वहाँ नहीं था। सब लोग सोते से उठ गए थे और सारे घर में जाने माने तरीकों से उसे ढूँढ़ने की कोशिश कर डाली लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। दूसरे दिन वह पडोस के घर में अलमारी में रखी हई अचारदानी से लिपटा हुआ दिखाई दिया और छुपन छपाई का खेल खेलता हुआ आखिर में मारा गया।

और अब यह मेरा तजुर्बा ही था जिसके कारण इस बात को वहम समझ कर मैंने अनदेखा नहीं किया। यह एक पहेली बनकर ही रह गई होती यदि मैं ने यह ज़िद न की होती कि जो मैं ने देखा था वह कोई वहम नहीं था। इस के अलावा मुझे अपने पड़ोसी जो सामने वाले फ्लैट में आज कल अकेले थे उनकी भी चिन्ता थी। अकेले होने के कारण वह अक्सर रात देर से ही आया करते थे। मुझे यह चिन्ता सता रही थी कि यदि वह देर से आए और दरवाज़ा खोल के अंदर गए तो हो सकता है कि वह सांप जो शायद उनके दरवाज़े से उनके घर में घुस गया हो उन पर आक्रमण कर दे। उनकी जान के खतरे को ध्यान में रखकर मैं ने यह तय किया कि मैं अपने फ्लैट का दरवाज़ा खुला रखूंगा ताकि मैं सोफे पर बैठकर अपने दरवाज़े से उनके सामने वाले दरवाज़े पर नज़र रख संकू और जैसे ही वह वापस लौटें उन्हें अंदर जाने से रोक सकूं। यह वह ज़माना था जब मोबाइल फोन साथ में नहीं हुआ करते थे और लोगों से संपर्क करना आमतौर से संभव नहीं होता था। इस बीच में मैं ने अपने अड़ोसी पड़ोसियों को बालकोनी से सावधान कर दिया था। फिर अपने पौराणिक ज्ञान का फायदा उठाते हुए सांप की चाल धीमी करने के लिए मैंने राई के दाने अपने दरवाज़े से लेकर ऊपर और नीचे जीने की सीढ़ियों पर फैला दिए।

कई घंटे गुज़र गए। सूरज क्षितिज में जाकर छिप चुका था। चारों ओर अंधेरा छाने लगा था। लेकिन मेरे सामने वाले पड़ोसी का कोई पता न था। लेकिन जो

एक सांप की झलक से शुरू हुआ डर, जिम्मेदारी और भ्रम में बदल गया। जब खतरा टल गया, तो एक फुसफुसाहट ने सब कुछ बदल दिया—"इसे मारना नहीं चाहिए था।" यह कहानी है डर, अनुभव और पश्चाताप के टकराव की।

मैंने देखा वह देख कर एक बार तो हम सब सहम गए। एक लम्बा सांप सामने वाले फ्लैट के दरवाज़े के नीचे से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया और मेरे फ्लैट के खुले हुए दरवाज़े की तरफ बढ़ा। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं कैसे उसे रोंकू। लेकिन हमारी किस्मत ने हमारा साथ दिया और वह अपने आप ही नीचे की ओर सीढ़ियों से उतरने लगा। उसकी चाल बहुत धीमी थी क्योंकि उसका शरीर राई के दानों से प्रभावित था। वह जैसे जैसे नीचे बड़ा मैं ऊपर जाने वाले जीने पर चढ़कर सेकंड फ्लोर पर पहुँच गया और उसे नीचे आहिस्ता आहिस्ता उतरता हुआ देखता रहा। परन्तु मैं यह नहीं समझ पा रहा था उसे समाप्त कैसे करूं।

शायद मेरे डावां डौल मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करने दूसरे माले के फ्लैट पर रहने वाली महिला मेरे पीछे आ कर खड़ी हुईं और मेरे हाथ में एक ईंट थमा कर मुझ से कहा "भाई साहब इसे मार दीजिए।" और मैं ने निशाना लेकर ईंट मारी। लेकिन निशाना चूक गया। फिर एक के बाद एक ईंट ईंटों के ढेर से मैं हाथ में लेता रहा और सांप पर निशाना ताक कर फेकता रहा। लेकिन ईंटों के ढेर के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए वह सांप चलता गया। फिर आखिर में एक ईंट निशाने पर ठीक बैठी और मैं उसे कुचल पाने में सफल हो गया। और जब मैं ईंटें फेकते फेकते रुका तबही उन महिला ने मेरे कान में धीरे से कहा "इसे मारना नहीं था।"

आखिर जब हमें यकीन हो गया कि वह मर गया तो हम नीचे आए और सड़क के किनारे एक गड्ढा खोद कर उसे दफना दिया। लोग उस स्थान पर इकट्ठे तो हुए और मैं यह सोच रहा था कि आखिर यह लोग उस वक़्त कहाँ थे जब सांप के साथ मैं घमासान युद्ध कर रहा था। उनमें से किसी ने हमारे मन की बात समझकर कहा "हम तो यह समझ रहे थे कि पड़ोसियों के बीच लड़ाई हो रही है।" मुझे यह बात सुन कर बड़ा अज़ीब लगा। लेकिन फिर भी मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ। ज़ाहिर था लोग आपस में घमासान युद्ध के काफी आदी हो चुके हैं।

उत्कृष्ट योगदान के लिए युवा महिला अचीवर्स सम्मानित

~सुदामा पाल

सुदामा पाल

मित्र, सहकर्मी और परिवार के सदस्य अपने चाहने वालों के जीवन को कई तरीकों से याद करते हैं, जैसे कि स्मरण सभाएँ, अख़बारों में विज्ञापन और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर पोस्ट। जिनके पास पैसे हैं वे पदक, छात्रवृत्तियाँ देते हैं और धर्मशालाओं और निजी स्कूलों में कमरे बनाने में भी योगदान देते हैं।

हालाँकि, स्वैच्छिक सामाजिक कार्य तरीके से याद करता है। सेवानिवृत्त नौकरशाहों और पेशेवरों और उनके दोस्तों द्वारा एक पारिवारिक ट्रस्ट के रूप में शुरू किया गया, यह फ़ाउंडेशन समाज को वह वापस देना चाहता है जो समाज ने उन्हें सम्मान, सम्मान और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के रूप में दिया था। और जब आप वापस देते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से उन लोगों को देना चाहेंगे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन की बाधाओं को पार करते हुए और यथास्थिति द्वारा संचालित व्यवस्था के मानदंडों को चुनौती देते हुए, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की है। फाउंडेशन के महासचिव राजीव माथुर कहते हैं, "हम जश्न नहीं मनाते, बल्कि हम उन लड़कियों को चुनते हैं और पुरस्कृत करते हैं जिनके साहस और दृढ़ संकल्प के बारे में उनके परिवारों के अलावा कोई नहीं जानता और किसी को इसका एहसास भी नहीं होता।

के लिए एक गैर-लाभकारी स्वैच्छिक संगठन, MBKM फ़ाउंडेशन अपने संस्थापक सदस्यों में से एक को एक अलग फाउंडेशन उन युवा महिलाओं को चुनता है जो सामान्य पृष्ठभूमि से आती हैं और जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से,

फाउंडेशन के संरक्षक 85 वर्षीय टेक्नोक्रेट आरएस अत्रोली, जिन्होंने सिविल इंजीनियर के रूप में

पश्चिमी रेलवे नेटवर्क के विस्तार में

महत्वपूर्ण योगदान दिया है, कहते हैं,

"ऐसी लड़कियों को चुनकर और उन्हें वीआईपी द्वारा आयोजित समारोह में पुरस्कृत करके हम समाज को यह संदेश देना चाहते हैं कि न केवल समाज के कमजोर वर्गों की प्रतिभा को पहचाना जाए और पुरस्कृत किया जाए, बल्कि इन पुरस्कार विजेताओं को इस सामाजिक-आर्थिक स्तर के अन्य लोगों के लिए एक आदर्श के रूप में पेश किया जाए।"

पेशे से वकील श्री सीके श्रीवास्तव, जिन्होंने फाउंडेशन की स्थापना के लिए सभी आवश्यक कार्य किए, कहते हैं कि फाउंडेशन ने डॉ. रमा सहारिया की स्मृति में पुरस्कारों की स्थापना की है, जो एक प्रख्यात शिक्षाविद् थीं और जिन्होंने यूपी सरकार के तीन कॉलेजों में प्रिंसिपल के रूप में कार्य किया था। पेशे से मनोवैज्ञानिक, डॉ. रमा के मन में हमेशा से ही सीमित साधन वाले परिवारों से आने वाली छात्राओं और मासिक अनुबंध के आधार पर काम करने वाले गरीब कॉलेज कर्मचारियों के लिए एक नरम कोना था।

"डॉ. रमा विविध रुचियों वाली व्यक्ति थीं। शिक्षाविद् होने के अलावा, वह महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर दैनिक और पत्रिकाओं के लिए लिखती थीं, एक अच्छी गायिका थीं और बुनाई, कढ़ाई और सिलाई जैसे कौशल के प्रति जुनूनी थीं। इसलिए, हमने उच्च शिक्षा, मीडिया लेखन/उत्पादन, सामाजिक कार्य और ललित/प्रदर्शन कला के चार क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार देने का फैसला किया।

पिछले शनिवार को दूसरे पुरस्कार समारोह में, निम्नलिखित युवा कामकाजी महिलाओं को उनके नाम के सामने उल्लिखित क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया:

• डॉ. प्रियंका – सहायक प्रोफेसर, उच्च शिक्षा में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित

• सुश्री ज़ेबा हसन – पत्रकार, मीडिया और लेखन में उपलब्धियों के लिए सम्मानित

• सुश्री साधना भारती - सामाजिक कार्यकर्ता, महिला अधिकार जागरूकता और सशक्तिकरण में उनके प्रयासों के लिए सम्मानित

• सुश्री रिम्पा कुमारी – संगीत शिक्षिका, ललित कला और संगीत में उत्कृष्टता के लिए विख्यात

नोएडा में आयोजित इस पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता पूर्व रक्षा सचिव डॉ. योगेंद्र नारायण ने की, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जाने-माने राजनेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय मौजूद थे। मंच पर मौजूद अन्य हस्तियों में

प्रख्यात शिक्षाविद् और मीडिया योगदानकर्ता प्रोफेसर लल्लन

प्रसाद भी शामिल थे।

ब्रह्माकुमारीज़ के राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक सुशांत और फाउंडेशन के पदाधिकारी। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र श्री सुनीत शास्त्री पिछले साल पहले स्मृति पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि थे।

अपने अध्यक्षीय भाषण में डॉ. योगेंद्र नारायण ने फाउंडेशन के प्रभावशाली काम की सराहना की। उन्होंने पर्यावरण क्षरण और बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दों पर चिंता व्यक्त की और सुझाव दिया कि पुरस्कार के भावी संस्करणों में पर्यावरण और कौशल विकास के क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को भी सम्मानित किया जाना चाहिए। फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रदीप माथुर ने इस संवाददाता को बताया कि फाउंडेशन की अगली कोर कमेटी की बैठक में डॉ. नारायण के सुझाव पर विचार किया जाएगा।

मुख्य अतिथि और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुबोध कांत सहाय ने सभा को संबोधित करते हुए आज के समाज में पारस्परिक संचार की बढ़ती कमी की ओर इशारा किया। उन्होंने छिपी हुई प्रतिभाओं की पहचान करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए एमबीकेएम फाउंडेशन की सराहना की और सभी से जागरूकता और साझा मूल्यों के माध्यम से अधिक से अधिक महिलाओं को प्रोत्साहित करने और

सशक्त बनाने का आग्रह किया। उन्होंने सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को बधाई दी और उन्हें प्रेरणा की किरण बनने के लिए प्रोत्साहित किया।

इस अवसर पर पुरस्कार विजेताओं की चयन समिति की अध्यक्ष प्रोफेसर (डॉ.) अर्चना वर्मा और नवरतन फाउंडेशन के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता अशोक श्रीवास्तव ने भी अपने विचार रखे। जाने-माने पत्रकार केबी माथुर, सैयद नूरुज्जम, सुधांशु मिश्रा, अनिल माहेश्वरी, खलीक अहमद, लक्ष्मण राय, साकेत दिनकर और डॉ. मुजफ्फर गजाली ने भी अपने दृष्टिकोण साझा किए और इस पहल का समर्थन किया।

कर्नल मेघा ने दो घंटे के कार्यक्रम की तुलना की, जबकि डॉ. अपर्णा माथुर ने पुरस्कार विजेताओं की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए प्रशस्ति पत्र पढ़े।

एमबीकेएम फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रदीप माथुर और सिडनी निवासी सुश्री आकांक्षा माथुर ने अपने धन्यवाद ज्ञापन में कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी अतिथियों, प्रतिभागियों और फाउंडेशन के कर्मचारियों का हार्दिक आभार व्यक्त किया।

****

श्रद्धांजलि

नहीं रहे पूर्व ट्रिब्यून संपादक हरि जयसिंह

~मीडिया मैप न्यूज़

मार्च 29, 1940 को जन्मे पूर्व ट्रिब्यून संपादक हरि जयसिंह का 23 अप्रैल को 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे 1994 से 2003 तक नौ वर्षों तक द ट्रिब्यून के संपादक रहे, जो क्षेत्र में अस्थिरता और असुरक्षा का दौर था। हाल ही में अस्पताल में भर्ती होने के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। ट्रिब्यून ट्रस्ट के अध्यक्ष एन.एन. वोहम ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है।

हरि जयसिंह निडर पत्रकार थे जो सत्ता से सच कहने में कभी नहीं झिझके। संपादक के रूप में उन्होंने अखबार को हर मोर्चे पर मजबूती से संभाले रखा और द ट्रिब्यून की संस्थापक, महान दूरदर्शी सरदार दयाल सिंह मजीठिया की मूल पत्रकारिता की परंपराओं के प्रति सच्चे रहे।

हरि जयसिंह (मार्च 29 , 1940 - अप्रैल 23 , 2025)

अपने अंतिम संपादकीय में उन्होंने लिखा था: "प्रेस की स्वतंत्रता को अलग-थलग नहीं देखा जा सकता, और न ही यह कोई अंतिम उद्देश्य है। इसकी सामाजिक प्रासंगिकता है... स्वतंत्रता का संबंध न्यायपूर्ण कारणों के समर्थन, उदार और समतावादी शासन व्यवस्था के निर्माण तथा सत्ताधीशों की जवाबदेही से है।"

हरि जयसिंह आम आदमी के हक और सार्वजनिक सरोकारों के प्रबल पक्षधर थे। उनके साहसी लेखन ने पाठकों के मन को छुआ और सत्ता के गलियारों तक उसकी गूंज पहुंची।

चाहे वह हरियाणा के एक डीजीपी से जुड़ा रुचिका छेड़छाड़ मामला हो ("यह धर्म का प्रश्न है, श्री चौटाला", 5 दिसंबर 2000) या सार्वजनिक जीवन में नैतिकता पर

> हरि जयसिंह एक ऐसे संपादक थे जो निडरता से सत्ता से सवाल पूछते थे। "नो, माय लॉर्ड!" जैसे संपादकीय उनके नैतिक साहस की गवाही देते हैं। उन्होंने पत्रकारिता को न सिर्फ सूचना का माध्यम माना, बल्कि सामाजिक न्याय और जन सरोकारों की लड़ाई का औजार भी बनाया।

सवाल ("नो, माय लॉर्ड!", 5 मई 2002), हरि जयसिंह ने अपने विचार स्पष्टता से रखे।

> संपादक के रूप में उन्होंने न केवल अखबार को दिशा दी, बल्कि अपने साथियों को भरोसे और सहयोग का वातावरण दिया। वे पदानुक्रम से परे जाकर हर व्यक्ति को महत्व देते थे और ज़मीन से जुड़े इंसान थे, जिनकी संवेदनशीलता हर लेख और निर्णय में झलकती थी।

उनके नेतृत्व में द ट्रिब्यून ने नई ऊंचाइयों को छुआ और "जनता की आवाज़" के रूप में अपनी भूमिका को और भी सशक्त किया।

वर्ष 1998 में जब अधिकांश मीडिया घरानों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में सोचना भी शुरू नहीं किया था, तब हरि जयसिंह के दूरदर्शी मार्गदर्शन में द ट्रिब्यून ने अपनी ऑनलाइन संस्करण की शुरुआत की।

श्रद्धांजलि सभा

नई दिल्ली के गुरुग्राम स्थित नेशनल मीडिया सेंटर में 26 अप्रैल को हरि जयसिंह की स्मृति में एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें उनके परिजनों, पूर्व सहयोगियों, मित्रों और प्रशंसकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।वक्ताओं ने उन्हें न केवल एक उत्कृष्ट पत्रकार बल्कि एक अच्छे इंसान के रूप में याद किया। कहा गया कि उन्होंने द ट्रिब्यून, इंडियन एक्सप्रेस और नेशनल हेराल्ड जैसे प्रतिष्ठित अखबारों का संपादन किया और कभी भी जोखिम से डरकर अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया।

वे धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध थे और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मामले में कभी समझौता नहीं किया। वे न केवल एक श्रेष्ठ लेखक और संपादकीय योजनाकार थे, बल्कि एक संवेदनशील इंसान भी थे, जो कठिन परिस्थितियों में अपने सहयोगियों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे।

इस अवसर पर इंडिया टुडे के ग्रुप मैनेजिंग एडिटर राज चेंगप्पा, द ट्रिब्यून के पूर्व ब्यूरो प्रमुख के.वी. प्रसाद और वरिष्ठ पूर्व सहायक संपादक अश्वनी भटनागर सहित कई प्रमुख हस्तियां मौजूद थीं।

प्रभजोत सिंह ने कहा कि वे आम आदमी को महत्व देने वाला पेशेवर दिग्गज पत्रकार थे। वे एक ऐसे पेशेवर दिग्गज थे जिन्होंने आम आदमी को हमेशा सर्वोपरि रखा। उनके कार्य और दृष्टिकोण में सड़क पर चलने वाले व्यक्ति, पहचान की जद्दोजहद में लगे शिक्षित युवाओं और सरकारी उदासीनता के शिकार लोगों के लिए गहरा सम्मान और करुणा

> जब अधिकांश अखबार डिजिटल भविष्य से अनजान थे, तब हरि जयसिंह ने 1998 में द ट्रिब्यून का ऑनलाइन संस्करण शुरू कर मीडिया को नई दिशा दी। वे बदलाव के अग्रदूत थे, जिन्होंने पत्रकारिता को समय के साथ evolve किया, लेकिन मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया।

झलकती थी। वे राजनेताओं की संगत से दूर रहते थे और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से आए अपने पुराने मित्रों के साथ हँसी-मजाक करना

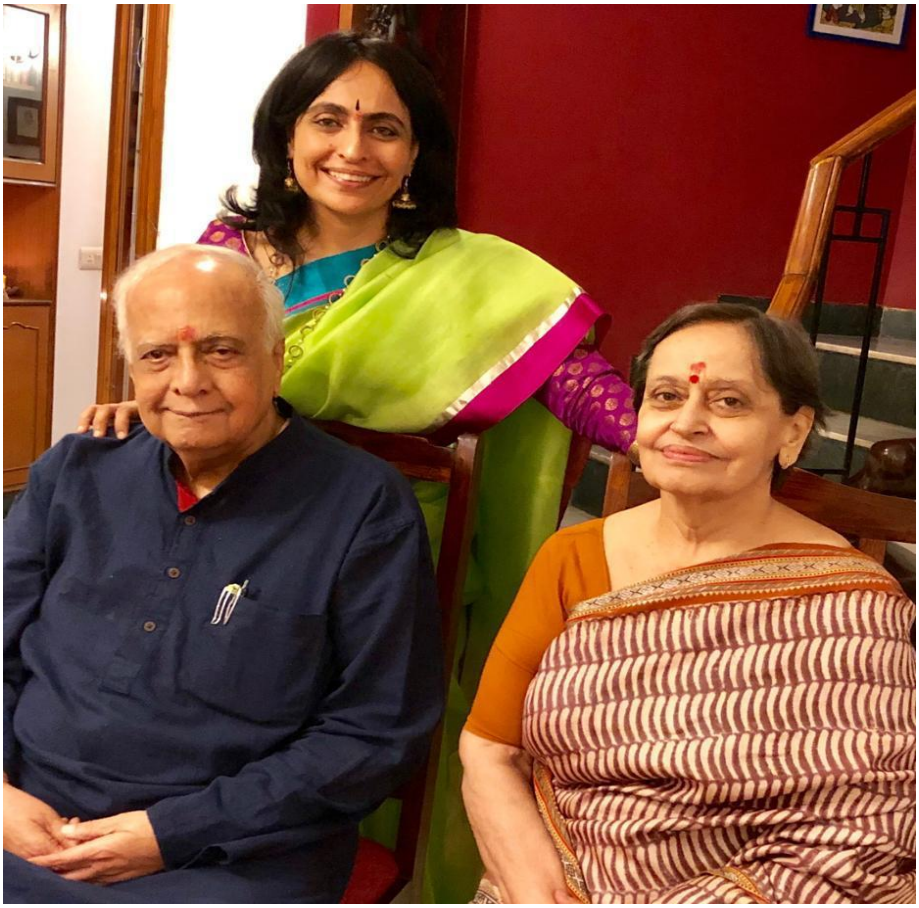

पसंद करते थे। उन्होंने कभी पदानुक्रम को अपने व्यवहार में आड़े नहीं आने दिया और हमेशा अपने अधीनस्थों पर भरोसा जताकर उनका साथ दिया।

मैंने उनके साथ आठ साल काम किया और उसके बाद भी उनके और उनके परिवार के साथ मेरे रिश्ते मधुर बने रहे। उनके जाने के बाद भी, उनके साथ बिताए गए हर पेशेवर और व्यक्तिगत क्षणों की मधुर स्मृतियाँ आज भी जीवंत हैं।

वे थे हरी जयसिंह, जिन्हें उनके ऐतिहासिक संपादकीय "नो, माय लॉर्ड" के लिए लंबे समय तक याद किया जाएगा। यह लेख उन कई रचनाओं में से एक था जिसने सत्ता के गलियारों को झकझोर दिया। पत्रकारिता की नैतिकता के प्रति पूरी तरह समर्पित और प्रेस की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक, वे जन्मजात नेता थे, जो हमेशा अग्रिम पंक्ति में रहकर नेतृत्व करते थे।

उन्होंने एक शिक्षित युवती के हक में आवाज उठाई जिसे केवल योग्यता के आधार पर नौकरी से वंचित कर दिया गया था। आम नागरिक के सम्मानजनक जीवन के अधिकार के लिए उन्होंने राज्य सत्ता से सीधा मुकाबला किया। वे द ट्रिब्यून के संपादक रहे — उत्तर भारत का सबसे पुराना और सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला अंग्रेज़ी दैनिक।

उनका स्पष्ट निर्देश था कि "चंडीगढ़ ट्रिब्यून" जनता केंद्रित हो और युवा वर्ग पर ध्यान दे। उन्होंने हमेशा सुझावों और नए विचारों के लिए द्वार खुले रखे। वे सरल, ज़मीन से जुड़े व्यक्ति थे, और इसी वजह से पाठकों और पत्रकारों के बीच बेहद लोकप्रिय रहे। उनके लेख "फ्रैंकली स्पीकिंग" सबसे अधिक पढ़े जाते थे।

उनकी ईमानदारी, विचारशीलता और निर्भीकता ने उन्हें भारतीय पत्रकारिता में एक ऊँचा स्थान दिलाया। वे एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के प्रमुख भी बने। हाल ही में उन्हें एक स्ट्रोक आया और कुछ दिनों के इलाज के बाद वे इस दुनिया से विदा हो गए। अपने पीछे वे पत्नी नीना, बेटा राहुल, बेटी भावना और अनगिनत यादें छोड़ गए।

हरि जयसिंह आम आदमी के पक्ष में खड़े रहने वाले पत्रकार थे। शिक्षा, न्याय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर उन्होंने निर्भीकता से कलम चलाई। उनका मानना था कि प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ है—सत्ताधीशों की जवाबदेही तय करना और न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था को मजबूत करना।

RNI NO. : UPHIN/2016/68336

See Media Map Website

Website link: www.mediamap.co.in

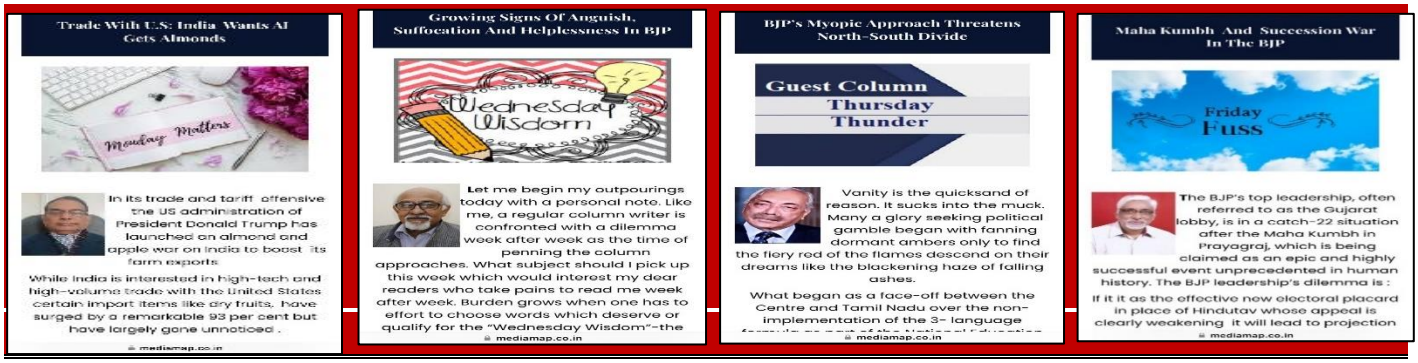

View Media Map YouTube

Media Map News

जनसंवाद 7 : खानपान पर रोक क्यों? Ep- 124
3 views • 4 hours ago

जन संवाद 6 : नेहा हो या कुणाल, व्यंग्य से क्यों डरना? Ep- 123
4 views • 4 hours ago

विविधा 15 : जज को भी छह महीनों की सजा : Ep- 122
27 views • 21 hours ago

विविधा- 14 : कंपनी की तानाशाही - आपके प्रोडक्ट को ख़राब कर रहें हैं। Ep- 121
6 views • 23 hours ago

आर्थिक सहयोग की अपील

उदार लोकतंत्र और गैर-सांप्रदायिक विश्वास के दर्शन से जुड़ा, मीडियामैप समाचार नेटवर्क एक गैर-व्यावसायिक संगठन है। हम आप जैसे गंभीर और समझदार पाठकों को संबोधित करना चाहते हैं। वरिष्ठ मीडियाकर्मियों के समूह द्वारा किया गया यह एक स्वैच्छिक प्रयास है, जिसका किसी राजनीतिक, सामाजिक या व्यावसायिक समूह से कोई संबंध नहीं है। मीडिया मैप के प्रकाशन को निरंतर व सुचारु रूप से जारी रखने हेतु आपका सहयोग आवश्यक है।

- ***State Bank of India***
- ***Account No. 43812481024***
- ***IFSC # SBIN0005226***
- ***प्रस्तुत QR कोड को स्कैन करें।***

प्रकाशक
MBKM Foundation, एक पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन

पंजीकृत कार्यालय
फ्लैट नंबर: 2332, सेक्टर-डी, पॉकेट-2, वसंत कुंज, दक्षिण दिल्ली

Advt.

Scholars Destination

PLEASE CONTACT

9045005700 | 9910322682 | www.sdmotel.com | info@sdmotel.com

BHALUGAAD WATERFALL

KAINCHI DHAM

MUKTESHWAR DHAM

CHAULI KI JALI